A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 20 नवम्बर, 2025
भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित
वर्ष 23, अंक 80, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

टूटता पाकिस्तानः सेना ने संविधान को कब्र में भेजा

ओंकारेश्वर पांडेय

देशों की तबाही अचानक नहीं होती। न कोई रात में उठकर यह घोषणा करता है कि संविधान मर चुका है, और न कोई सुबह अख़बार के पहले पन्ने पर यह लिखता है कि न्यायपालिका का अंत हो गया। यह सब धीरे-धीरे होता है। परत दर परत, साल दर साल, जब तक एक दिन ऐसा नहीं आता कि बची-खुची संस्थाएँ स्वयं ही स्वीकार कर लें कि अब प्रतिरोध संभव नहीं।

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जिन दो सबसे सम्मानित न्यायाधीशों जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एक-एक कर अपने पदों से इस्तीफा दिया, वह भी एक साधारण विरोध नहीं है; यह पाकिस्तान की न्यायिक स्वतंत्रता की लाश पर लिखा गया दो-लाइन का अंतिम बयान है। लेकिन इस उथल-पुथल को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा। यानी फ़ैज़ाबाद धरना, नवंबर 2017। वही धरना, वही ज़ख्म, जो आठ साल बाद संविधान की कब्रगाह तक पाकिस्तान को खींच लाया। फैज़ाबाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद और रावलपिंडी को जोड़ने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका और चौक (इंटरचेंज) है। 2017 की ठंडी नवंबर की एक सुबह इसी मोड़ पर एक ऐसा राजनीतिक नाटक शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान का रुख बदल दिया।

नवंबर 2017 में, एक धार्मिक-राजनीतिक पार्टी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) ने इस चौक को पूरी तरह बंद कर दिया। उन्होंने राजधानी के आवागमन को ठप्प कर दिया, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी हुई। तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान (TLP), एक कट्टर धार्मिक-राजनीतिक संगठन, अचानक राजधानी के दरवाज़े पर खड़ा था। हज़ारों लोगों के साथ। पूरा देश एक ऐसे टकराव में डूबा हुआ जिसमें हर कोई जानता था कि सरकार की नहीं, किसी और की परीक्षा हो रही है।

कहा गया कि चुनाव अधिनियम की 'ख़त्म-ए-नबूवत' की शपथ में बदलाव ने यह तूफ़ान खड़ा किया। पर यह कोई धार्मिक आक्रोश नहीं था; यह एक संदेश था। एक चेतावनी कि अगर सत्ता भूल जाए कि असली मालिक कौन है, तो 'सड़कें' उसे याद दिलाने आ सकती हैं। शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी की सरकार इस संकट के सामने पिघल गई। जब सरकार गिरने जैसी हालत में थी, तब मंच पर प्रवेश हुआ पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली संस्थान का। ISI और MI के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें उस समय के DG-MI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर भी शामिल थे, 'बातचीत' के लिए धरने में पहुँचे। और फिर वह दृश्य जिसे पाकिस्तान आज भी यूट्यूब पर बार-बार देखता हैः वर्दीधारी अधिकारी प्रदर्शनकारियों में लिफ़ाफ़े बाँट रहे थे। सौदे तय किए जा रहे थे। धार्मिक उन्माद का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा था। सरकार ने घुटने टेक दिए। क़ानून मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया। टीएलपी विजयी होकर घर लौटी। हर किसी ने समझ लिया कि असल सत्ता किसके हाथ में है।

दो साल बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वह किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जस्टिस क़ाज़ी फ़ाएज़ ईसा की बेंच ने फ़ैज़ाबाद धरने पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह पाकिस्तान की सत्ता संरचना के केंद्र पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। जजों ने लिखा कि खुफ़िया एजेंसियों ने संविधान से परे जाकर काम किया। उन्होंने 'अदृश्य हस्तक्षेप' को बेनक़ाब किया। कई अधिकारियों का नाम सीधे-सीधे दर्ज हुआ। कुछ संस्थाओं की भूमिका पर कड़ी टिप्पणी हुई। दायरे में DG-ISI, DG-MI और पूरी सुरक्षा व्यवस्था की परोक्ष भूमिका आ गई। और यहीं से कहानी की दिशा बदल गई। यह फैसला पाकिस्तान की सैन्य-न्यायिक राजनीति के नियमों के विरुद्ध था। यह वह साहसिक कदम था जो 2007 के वकील आंदोलन की याद दिलाता था। लेकिन इस बार प्रतिद्वंद्वी और भी अधिक शक्तिशाली, अधिक रणनीतिक, और अधिक छुपा हुआ था। नतीजा तय थाः ऐसी न्यायपालिका दोबारा नहीं रहने दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद मामले की स्वतः सुनवाई की। फैसले में कोर्ट ने साफ कहा- सेना और खुफिया एजेंसियों ने 'गैर-जिम्मेदार' और 'असंवैधानिक' भूमिका निभाई। उन्होंने एक 'अघोषित' भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर किया। यह फैसले ने दिखा दिया कि जब देश की राजधानी बंधक बनी हुई थी, तो असली सौदेबाजी प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं, बल्कि सेना प्रमुखों और TLP नेताओं के बीच हो रही थी। जनरल आसिम मुनीर (अब सेना प्रमुख) और उनके संस्थान के लिए यह फैसला एक शर्मिंदगी और जख्म का कारण बना। आज 2025 में, सुप्रीम कोर्ट को तोड़ने वाला 27वां संशोधन, उसी जख्म का बदला माना जा रहा है। सेना प्रमुख एक ऐसी न्यायपालिका नहीं चाहते, जो उनके काम में दखल दे सके। 2024 में आया 26वाँ संशोधन यानी पहला वार। यह न्यायपालिका की सामूहिक ताक़त को कमजोर करने का परीक्षण था। जस्टिस मंसूर अली शाह अपने पत्र में लिखते हैं कि उन्होंने तब उम्मीद की थी कि 'भीतर से' प्रतिरोध होगा। पर हवा का रुख तेजी से बदल रहा था। 2025 का 27वाँ संशोधन तो विध्वंस का अंतिम चरण था। इसने सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में बाँट दिया, एक 'अपील अदालत' और एक नया 'संवैधानिक न्यायालय' जिसमें जजों की नियुक्ति पर कार्यपालिका का भारी प्रभाव रहेगा। यह संविधान के भीतर रेंगता हुआ तख़्तापलट था, एक 'कानूनी' कू। इसके खिलाफ जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तीफ़ा एक बेहद शांत, सटीक, कानूनी प्रहार थाः उन्होंने कहा, 'एक कटे-फटे न्यायालय में बने रहना संविधान के अपराध में मौन साझेदारी है।' एक न्यायाधीश जो संविधान की रक्षा न कर सके, वह न्यायाधीश रह भी कैसे सकता है? जस्टिस अतर मिनल्लाह का पत्र उससे भी अधिक तीखा, मानवीय और झकझोर देने वाला था। उन्होंने लिखाः 'वह संविधान जिसे मैंने बचाने की शपथ ली थी, अब अस्तित्व में ही नहीं है।' और फिर वह वाक्य, जो पाकिस्तान की न्यायपालिका पर एक स्याह रेखा खींच देता है- 'अब न्यायाधीश का वस्त्र पहनना विश्वासघात का प्रतीक बन चुका है।' ये इस्तीफे नौकरियों से त्यागपत्र नहीं, बल्कि लोकतंत्र के शव पर लिखे अंतिम शब्द हैं। आज का पाकिस्तान एक अधिक परिष्कृत, अधिक नियंत्रित, अधिक तकनीकी तंत्र है, जहाँ सत्ता गनरूम से नहीं, कानूनी संशोधनों और राजनीतिक मंचन से चलाई जाती है। जनरल आसिम मुनीर, ने पूरे संविधान को संक्रमित कर दिया है। अब कोई न्यायालय प्रश्न नहीं पूछेगा। अब कोई फैसला सत्ता को चुनौती नहीं देगा। अब पाकिस्तान में संविधान नहीं, बल्कि उसकी यादें बची हैं।

इस संविधान संशोधन के खिलाफ देश भर के वकीलों के संगठन और विपक्षी दल सड़कों पर उतर रहे हैं। इसे 'न्यायपालिका की हत्या' का नाम दिया जा रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान को एक ऐसे देश के तौर पर देखा जाएगा, जहाँ लोकतंत्र का अंतिम गढ़ भी ढह गया। पाकिस्तान एक नए अँधेरे में प्रवेश कर चुका है, और पूरी दुनिया खामोश खड़ी देख रही है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

शरद की सुबह

आज यह जो आम का पौधा लगाया है मैंने
जब तक देह देगी साथ
सनेह सीचूँगा इसे
किसी दिन धरा के वक्ष पर
वृक्ष बनेगा यह
मोक्ष नहीं
हर बार लौटने को जीवन चाहूँगा मैं
किसी शाख पर कूक भरूँगा कोयल बन
तोता–चिड़िया बनकर चखूँगा
चाहूँगा जितने फल
लौटा यदि लेकर यही देह
बैठूँगा इसकी ही छाँव में
इसी के फल होंगे मेरी चाव में शामिल
अब तो आज भूलने लगा हूँ कल का
फिर किसे याद रहता है
जन्म–जन्मांतर
मैं सचमुच भूल जाऊँगा
यहाँ आम का पौधा लगाया था मैंने

- वसंत सकरगाए

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छतरपुर में होटल द राजगढ़ पैलेस का शुभारंभ किया

टूरिस्ट हेली सर्विस का उठाएं भरपूर लाभ

- सालभर में 13.41 करोड़ से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश आए
- प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश को दी वाराणसी से खजुराहो वंदे भारत ट्रेन की सौगात
- भारत में चिन्हित की गई 17 आइकोनिक सिटीज में खजुराहो भी शामिल
- राजगढ़ पैलेस होटल के जरिए स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार

भोपाल/खजुराहो (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि विश्व धरोहर स्थल खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। खजुराहो में एयरपोर्ट तो पहले से है ही, अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी से खजुराहो नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दे दी है, जिससे बुंदेलखंड की शान मतंगेश्वर महादेव सीधे काशी विश्वनाथ से जुड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पर्यटकों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए नई पीएमश्री हेली टूरिस्ट सर्विस शुरू की है। इसके अलावा प्रदेशवासियों को इंटर स्टेट हवाई सेवा और एयर एंबुलेंस की सुविधा भी मिल रही है। पर्यटक इन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या में 526 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। बीते साल 13 करोड़ 41 लाख से अधिक पर्यटक मध्यप्रदेश की धरती पर आए। हमारी पर्यटन प्रोत्साहन योजनाओं के कारण भविष्य में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को खजुराहो में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने खजुराहो में 'होटल द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस' का दीप प्रज्ज्वलन एवं फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर ओबेरॉय ग्रुप के स्वामी श्री अर्जुन ओबेरॉय ने पुष्पगुच्छ एवं शॉल ओढाकर मुख्यमंत्री डॉ. यादव का आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खजुराहो का ईश्वर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। ओबेरॉय ग्रुप के राजगढ़ पैलेस होटल के माध्यम से आज खजुराहो समृद्धि के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। राज्य सरकार बुंदेलखंड के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। खजुराहो की प्राचीनतम स्थापत्य कला को देखने के लिए पूरी दुनिया खिंची चली आती है। खजुराहो महाराजा छत्रसाल की राजधानी रही है। बुंदेलखंड में आल्हा-ऊदल की वीरता की कहानियां जोश से भर देती हैं। यहां 70 एकड़ में यह भव्य होटल बनकर तैयार हुआ है, जिससे पर्यटकों को तो लग्जरियस फेसिलिटी मिलेगी ही, स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा।

क्षेत्रीय सांसद श्री वीडी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। खजुराहो एक विश्व धरोहर है, यहां रोजाना दुनियाभर के पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में 17 आइकोनिक सिटी चिह्नित की हैं, इनमें खजुराहो भी शामिल है। यहां नजदीक ही पन्ना टाइगर रिजर्व को देखने के लिए भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खजुराहो को हवाई सेवा के साथ सुपरफॉस्ट ट्रेन वंदे भारत की रेगुलर कनेक्टिविटी भी दे दी है। पन्ना में हीरे तो मिलते ही हैं, भविष्य में राजगढ़ पैलेस होटल इंडस्ट्री का डायमंड बनकर उभरेगा।

कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार, विधायक श्री अरविंद पटेरिया, विधायक श्रीमती ललिता यादव, विधायक श्री राजेश शुक्ला, विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती विद्या अग्निहोत्री, अपर मुख्य सचिव संस्कृति एवं पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला, डी आईजी विजय खत्री, कलेक्टर श्री पार्थ जैसवाल, पुलिस अधीक्षक श्री अगम जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ओबेरॉय ग्रुप के स्टॉफ मेंबर्स उपस्थित रहे।

एसआईआर का सर्वे करने गई टीम पर हमला

नायब तहसीलदार और बीएलओ को मारे पत्थर, जान बचाकर भागे अधिकारी

रतलाम (नप्र)। रतलाम के बासिंद्रा में बुधवार को एसआईआर का सर्वे करने गए प्रशासन की टीम पर हमला हो गया। ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। हमले में नायब तहसीलदार रामकलेश साकेत और बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ घायल हो गए। टीम ने भी अपनी जान बचाई है। दोनों घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज लाया गया है। पूरा मामला सैलाना विधानसभा क्षेत्र का है। तीन आरोपियों द्वारा किए गए हमले की सूचना मिलते ही एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव, एएसपी राकेश खाखा, सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया और अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली।

तीनों आरोपी उमर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं और घटना के समय शराब के नशे में थे। पुलिस ने इनमें से दो आरोपियों–सायसिंह (28) और बापी ताड़ (55)–को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरा आरोपी शोकसिंह (31) फरार है।

नशे में धुत थे आरोपी

घायल बीएलओ विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि घटना बासिंद्रा के पास जुलवानिया में हुई, जब तीन नशे में धुत लोग बाइक से आए और बिना कारण गाली–गलौज करने लगे। उनके पास मछली भी थी और वे लगातार पत्थर फेंक रहे थे। इस दौरान तहसीलदार और पटवारी ने एक–दूसरे को बचाया। विक्रम सिंह के हाथ और पेट में चोट आई है। उन्होंने कहा कि पत्थर फेंकते समय पटवारी ने तहसीलदार को धक्का देकर बचाया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई।

नीतिश सीएम, सम्राट और विजय सिन्हा बनेंगे डिप्टी सीएम

- बिहार में हो गया फैसला, शपथ ग्रहण समारोह आज दोपहर 1.30 बजे

पटना (एजेंसी)। नीतिश कुमार कल यानी गुरुवार को दोपहर 1.30 बजे गांधी मैदान में सीएम पद की शपथ लेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह जानकारी दी है।

बुधवार को सीएम हाउस में जदयू के विधायक दल की मीटिंग हुई। बैठक में नीतिश कुमार को विधान मंडल दल का नेता चुन लिया गया है। इससे पहले बुधवार सुबह 11 बजे पटना के बीजेपी ऑफिस में विधायक दल की बैठक हुई। इसमें सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया है। विजय सिन्हा को विधानमंडल का उपनेता चुना गया है। अब ये तय हो गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ही नई सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। इधर, सूत्रों के अनुसार चिराग पासवान ने एनडीए में 2 मंत्री पद और डिप्टी सीएम पद की डिमांड रखी है। चिराग अपने बहनोई अरुण भारती का नाम बढ़ा सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में एलजेपी (आर) ने 19 सीटें जीती हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव से पहले केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आपस में चर्चा की।

करंट से किसान दंपत्ति की मौत

थावर नदी में मोटर हटाते समय हादसा, पति को बचाने में चपेट में आई महिला

मंडला (नप्र)। मंडला जिले के पिंडरई चौकी क्षेत्र में बुधवार को पानी की मोटर निकालते समय करंट लगने से एक दंपत्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा। हादसे से गांव में शोक का माहौल है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

नदी में उतरकर मोटर निकाल रहे थे– जानकारी के अनुसार, ग्राम अतरिया निवासी किसान राधे कुलस्ते (36) और उनकी पत्नी सीमा कुलस्ते (30) की थावर नदी में करंट लगने से मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि राधे कुलस्ते नदी में उतरकर मोटर निकाल रहे थे, तभी मशीन में अचानक तकनीकी खराबी आ गई।

दोनों की मौके पर मौत

इसके चलते पानी में तेज करंट फैल गया और राधे उसकी चपेट में आ गए। पति को बचाने की कोशिश में पत्नी सीमा भी नदी की ओर दौड़ीं, लेकिन वे भी करंट की चपेट में आकर मौके पर ही गिर पड़ीं। इस दौरान दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना जरूरी नहीं है

- भागवत बोले-देश पर गर्व करने वाला हर व्यक्ति हिंदू
- कहा- यह शब्द धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक परंपरा

गुवाहाटी (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को कहा- भारत और हिंदू एक ही हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी सभ्यता पहले से ही इसे जाहिर करती है। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के दौरान भागवत ने कहा कि जो भी भारत पर गर्व करता है, वह हिंदू है। हिंदू सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं बल्कि एक सभ्यता गत पहचान है, जो हजारों साल की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ी है। संघ चीफ सोमवार को तीन दिवसीय यात्रा के लिए असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। बुधवार को भागवत ने एक युवा सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद 20 नवंबर को मणिपुर के लिए रवाना होंगे। असम में डेमोग्राफिक चेंज पर मोहन भागवत ने कहा- हमें आत्मविश्वास, सतर्कता और अपनी जमीन-संस्कृति से मजबूत लगाव रखना चाहिए। साथ ही कहा कि समाज के

सभी वर्गों को मिलकर निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। पूर्वोत्तर को उन्होंने भारत की एकता में विविधता का बेहतरीन उदाहरण बताया। कहा कि लचित बोरफुकन और श्रीमंत शंकरदेव जैसे व्यक्तित्व सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व रखते हैं। सभी भारतीयों को प्रेरित करते हैं।

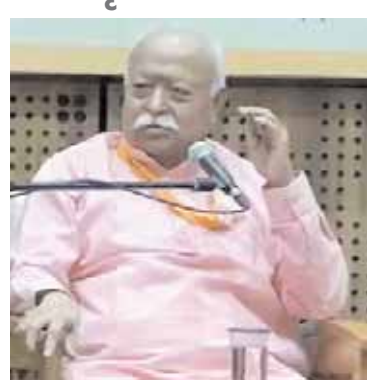

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 20 नवंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया गया

● बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला के मर्डर का लगा है आरोप

मुंबई/नई दिल्ली (एजेंसी)। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से डिपोर्ट कर बुधवार को दिल्ली लाया गया। उसे एयरपोर्ट से सीधे पटियाला कोर्ट में पेश किया जाएगा। अमेरिका से कुल 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया है, इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। अभी इनके बारे में जानकारी नहीं मिली है। गैंगस्टर अनमोल अप्रैल, 2024 में बॉलीवुड स्टार सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग मामले में वांटेड आरोपी है। वह पिछले साल मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी भी है।

भारत को एसयू-57 फाइटर जेट्स देने को रूस तैयार

● तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेगा

मॉस्को (एजेंसी)। भारत को एसयू-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने के लिए रूस तैयार हो गया है। दुबई एयर शो में रूसी कंपनी रॉस्टेक के सीईओ सेर्गेई केमेजोव ने कहा कि वे इन फाइटर जेट्स की तकनीक भी बिना शर्त ट्रांसफर करेंगे। रूसी एसयू-57 जेट्स को अमेरिका के एफ-35 का तोड़ माना जाता है। एसयू-57 की तरह एफ-35 भी 5वीं जेनरेशन का लड़ाकू विमान है। अमेरिका लंबे समय से भारत को एफ-35 बेचना चाह रहा है। रूस से यह आश्वासन ऐसे समय आया है जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने हाल ही में मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन अगले महीने भारत आने वाले हैं।

एसआईआर के लिए गांव-गांव घूम रहे एसपी विधायक फहीम

● यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने खिलाई थी बीवी की कसम

मुरादाबाद (एजेंसी) बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान अक्सर चर्चा में रहते हैं। इसी साल मॉनसून सत्र में यूपी विधानसभा में बहस के दौरान यूपी जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पत्नी की कसम खाने की चुनौती दी थी। सपा के तेज तर्रार नेता फहीम इरफान इस समय अपने क्षेत्र में गांव-गांव साइकिल से टहल रहे हैं। यह एसआईआर को लेकर उनका मतदाताओं को जागरुक करने का अपना तरीका है। अपने इस अभियान के तहत वह बिलारी के ग्राम शाहपुर में यात्रा निकाली।

गरीबों को भी मिलनी चाहिए अंग प्रत्यारोपण की सुविधा

● सुप्रीम कोर्ट ने की जिंदगी को जिंदा रखने की शानदार पहल

सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बनाने के फैसले पर दी सहमति

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंग प्रत्यारोपण के लिए एक गाइडलाइन बनाने पर सहमति जताई है। इससे गरीब लोगों को जीवनरक्षक सर्जरी का समान अवसर मिल सकेगा। कोर्ट ने इस मामले में सरकार और याचिकाकर्ता से सुझाव मांगे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने सीजेआई बी. आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच को बताया कि अंगों की उपलब्धता का एक नेशनल डेटा ग्रिडहोना चाहिए।

इससे कतार में लगे संभावित मरीजों को पता चल सकेगा कि वे कहां खड़े हैं और उन्हें अंग मिलने की कितनी संभावना है। उन्होंने कहा कि हर राज्य में मरीजों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को अंग प्रत्यारोपण का मौका नहीं मिल पाता है। इसकी वजह यह है कि अंग प्रत्यारोपण करने वाले 90 फीसदी अस्पताल और क्लीनिक निजी क्षेत्र में हैं। ये सिर्फ अमीर और प्रभावशाली लोगों की पहुंच में है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों को निर्देश देना चाहिए कि वे हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक ऐसा अस्पताल खोलें, जहां गरीब मरीज किफायती दर पर अंग प्रत्यारोपण सर्जरी करवा सकें। उन्होंने अंग दान करने वालों में लिंगानुपातके असंतुलन पर भी चिंता जताई।

भारत में 'मोटिवेटेड एक्सीडेंट' के कई मामले

जस्टिस चंद्रन ने कहा कि दक्षिण भारत में मोटिवेटेड एक्सीडेंट के कई मामले सामने आए हैं। इन दुर्घटनाओं को इसलिए अंजाम दिया जाता है ताकि किसी इच्छुक मरीज को अंग मिल सके। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि यह ज्यादातर हाईवे पर होता है। केरल में इस मुद्दे पर एक फिल्म भी बनी थी, जिसकी पटकथा एक पुलिस अधिकारी ने लिखी थी, जो शायद इस घोटाले के बारे में जानता था। मेहता ने इन घटनाओं को हत्या के चौंकाने वाले मामले बताया। सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने मेहता, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक और वकील परमेश्वर से कहा कि वे बुधवार को अदालत में पेश करने के लिए आदेश में शामिल किए जाने वाले सामान्य बिंदुओं का मसौदा तैयार करें। यह गाइडलाइन इसलिए बनाई जा रही है ताकि गरीब और पिछड़े लोगों को भी अंग प्रत्यारोपण का समान अवसर मिले। अभी ज्यादातर निजी अस्पतालों में ही ये सर्जरी होती हैं, जो महंगी होती हैं।

एसआईआर पर इंदौर और भोपाल कलेक्टर को फिर फटकार

● ग्वालियर कलेक्टर के काम पर भी नाराजगी, ईसी डायरेक्टर बोलीं- सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई करेंगे

भोपाल (नप्र)। चुनाव आयोग ने एसआईआर की धीमी रफ्तार को लेकर एक बार फिर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत बड़े जिलों के कलेक्टरों को फटकार लगाई है। आयोग की डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना ने इन कलेक्टरों से कहा है कि अगर अगली मीटिंग से पहले एसआईआर डिजिटलाइजेशन में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है।

सक्सेना ने यह नाराजगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ली गई कलेक्टरों की मीटिंग में जताई है। उधर, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर भी इस काम में तेजी लाने के लिए कहा है। बुधवार को चुनाव आयोग के अफसरों ने एक बार फिर एसआईआर के गणना पत्रक वितरण और डिजिटलाइजेशन को लेकर कलेक्टरों के साथ संवाद किया।

छोटे जिलों की स्थिति में सुधार आया

इस दौरान यह जानकारी सामने आई कि शहडोल, उमरिया, अनूपपुर जैसे छोटे जिलों की हालत में सुधार आया है। इन जिलों में पिछली मीटिंग में गड़बड़ी पर कलेक्टरों को डांट पड़ी थी। इधर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में डिजिटलाइजेशन का प्रतिशत काफी कम है। इसके चलते चुनाव आयोग की डायरेक्टर शुभ्रा सक्सेना ने इन कलेक्टरों से नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अगली बैठक से पहले परफॉर्मेंस सुधार लें।

राज्यपाल ने आसियान समिति से कहा मध्यप्रदेश के साथ साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं

मध्यप्रदेश में स्थिर, सुरक्षित और उद्योग अनुकूल वातावरण : राज्यपाल मंगुभाई पटेल

भोपाल (नप्र)। राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने आसियान समिति से कहा है कि मध्यप्रदेश के साथ साझी विकास यात्रा की अपार संभावनाएं हैं। भारत और आसियान देश साझी सभ्यता वाले क्षेत्र हैं। मध्यप्रदेश और आसियान देशों के बीच सांस्कृतिक आत्मीयता, व्यापारिक समानता और सहयोग की संभावनाएँ अत्यंत मजबूत हैं। दोनों क्षेत्रों के पास युवा जनसंख्या की ऊर्जा, नवाचार की क्षमता, विविध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति तथा विकास के प्रति समान संवेदनशील दृष्टिकोण मौजूद है। प्रदेश के साथ व्यापार, निवेश, पर्यटन, शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में असाधारण और दीर्घकालिक साझेदारियाँ करने की अनंत संभावनाएँ हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में स्थिर, सुरक्षित और उद्योग अनुकूल वातावरण इस यात्रा को और अधिक अर्थपूर्ण बनाएगा।

● आसियान समिति का प्रतिनिधि मंडल राजभवन में मिला

राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में आमंत्रित आसियान समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ बुधवार को चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री चंद्रमौली शुक्ला भी मौजूद थे।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है। यह नीति भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साझा इतिहास, सांस्कृतिक जड़ों और भविष्य की समृद्ध साझेदारी को मजबूत करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के साथ व्यापारिक, निवेश, तकनीकी, सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों में निरंतर वृद्धि से पारस्परिक रिश्ते मजबूत होंगे। नए अवसर उत्पन्न होंगे। हमारी सहभागिता आने वाले वर्षों में एक नए अधिक विकसित युग का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार पारदर्शी नीतियों के साथ निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसी वर्ष प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा 18 नवीन इन्वेस्टर फ्रेंडली नीतियाँ लॉन्च की गईं। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में मध्यप्रदेश देश के उत्कृष्ट सुधारक राज्यों में शामिल है। मध्यप्रदेश की जनता सरलता, परिश्रम, सहिष्णुता और सौहार्द्र की मिसाल है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, क्योंकि इस राज्य की धड़कनें भारत की संस्कृति, परंपराएँ, प्रकृति, अध्यात्म, सामाजिक विविधता, आर्थिक क्षमता और आधुनिक विकास को समेटे हुए हैं। उन्होंने प्रदेश के नगरों, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के विकास और पर्यावरणीय संतुलन को रेखांकित किया। बताया कि राज्य में 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होने के कारण इसे देश की फूड बास्केट कहते हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने आसियान समिति नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को सांची की प्रतिकृति, स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। आसियान नई दिल्ली समिति के अध्यक्ष भारत में मलेशिया के उच्चायुक्त श्री दातो मुजफ्फर शाह मुस्तफा ने मध्यप्रदेश में प्रतिनिधि मंडल के गरिमामय स्वागत सत्कार के लिए आभार ज्ञापित किया।

राहुल गांधी के खिलाफ 272 रिटायर्ड जजों-अफसरों का लेटर

● कहा-चुनाव आयोग की छवि बिगाड़ रही कांग्रेस, राहुल 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके

नई दिल्ली (एजेंसी)। चुनाव आयोग पर लग रहे वोट चोरी के आरोपों पर देशभर के 272 रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने बुधवार को एक ओपन लेटर जारी किया है। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की गई है। लेटर में 16 पूर्व जज, 123 सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट (14 पूर्व राजदूत सहित) और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों के सिग्नेचर हैं। इन रिटायर्ड जजों और ब्यूरोक्रेट्स ने ओपन लेटर में आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं की साख कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनावश्यक अविश्वास फैलता है। लेटर में यह भी कहा गया कि चुनाव आयोग भारत की चुनाव प्रणाली का सबसे अहम स्तंभ है। उस पर बार-बार सवाल उठाना ठीक नहीं।

हमारी पीढ़ी के लिए दिव्य वरदान है सत्य साई का जन्म शताब्दी वर्ष

● प्रधानमंत्री मोदी पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह में हुए शामिल

कार्यक्रम में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय ने पीएम के पैर छुए, सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे

अमरावती (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को आंध्रप्रदेश के पुट्टपर्थी में सत्य साई बाबा के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा- श्री सत्य साई बाबा का यह जन्म शताब्दी वर्ष हमारी पीढ़ी के लिए सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक दिव्य वरदान है। आगे पीएम ने कहा कि आज भले ही वें हमारे बीच दैहिक स्वरूप में नहीं हैं, लेकिन उनकी शिक्षा, उनका प्रेम, उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही हैं। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इससे पहले मोदी सत्य साई बाबा का मंदिर और समाधि पर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा-पाठ की। जन्म शताब्दी इवेंट में सीएम मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे।

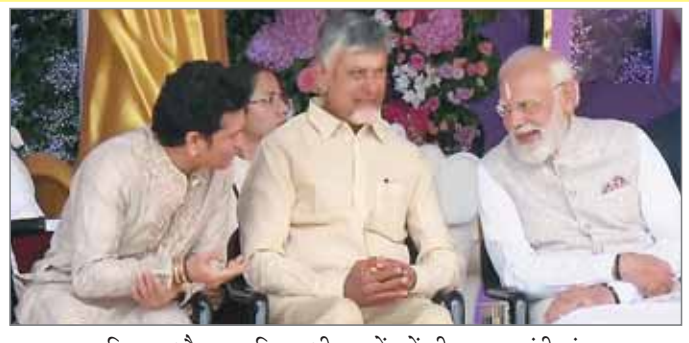

● मोदी बोले- सत्य साई बाबा का संदेश लोगों में दिखता है- पीएम मोदी ने कहा कि श्री सत्य साई बाबा का संदेश केवल पुस्तकों, प्रवचनों और आश्रमों की सीमाओं में नहीं रहा है। उनकी शिक्षा का प्रभाव लोगों के बीच दिखता है। आगे कहा कि आज भारत के शहरों से लेकर छोटे गांवों तक, स्कूलों से लेकर आदिवासी बस्तियों तक, संस्कृति, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का एक अद्भुत प्रवाह दिखाई देता है। बाबा के करोड़ों अनुयायी बिना किसी स्वार्थ के इस काम में लगे हैं। मानवसेवा ही माधव सेवा है, ये बाबा के अनुयायियों के सबसे बड़ा आदर्श है।

जर्मनी का हेलीकॉप्टर सेफ्टी सिस्टम अब सिर्फ भारत में बनेगा

भारत और जर्मनी ने एक बहुत बड़ी रक्षा उत्पादन कर ली डील

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत और जर्मनी ने बुधवार को दुबई एयरशो 2025 में एक हेलीकॉप्टर ऑब्सटैकल अवॉयडेंस सिस्टम (ओएएस) बनाने के लिए साझा कार्यक्रम की घोषणा की है। भारत की ओर से इसकी अगुवाई हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) और जर्मनी की आंशिक रूप से सरकारी स्वामित्व वाली हेन्सोल्ड्ट करेगी। इसके साथ ही भारत-जर्मनी के बीच रक्षा निर्माण के क्षेत्र में यह करीब तीन दशकों के बाद सबसे बड़ी और ऐतिहासिक डील है। इस कार्यक्रम के तहत भारत में ऑब्सटैकल अवॉयडेंस सिस्टम (ओएएस) बनाने का काम एचएएल के प्लांट में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पुण्यतिथि 8 दिसंबर से शुरू होगा। जानकारी के मुताबिक अगर जनरल रावत के हेलीकॉप्टर में इस तरह का सेफ्टी सिस्टम लगा होता तो शायद खराब मौसम में भी वह सुरक्षित लैंड कर सकता था। जर्मनी की कंपनी हेन्सोल्ड्ट अब अपने ओएएस का निर्माण सिर्फ भारत के माध्यम से ही करेगी और जर्मनी में इसका उत्पादन पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। पहले इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में लगाया जाएगा, फिर एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर में फिट होगा। बाद में अन्य प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल होंगे। यह बिल्ड टू स्पेक मॉडल पर साझा तौर पर बनाया जाएगा। इस डील में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजाइन पर बात हुई है।

ऑब्सटैकल अवॉयडेंस सिस्टम की जरूरत

हेलीकॉप्टर ऑब्सटैकल अवॉयडेंस सिस्टम की भारत को सबसे ज्यादा जरूरत लद्दाख, सियाचिन, नॉर्थ-ईस्ट, रेगिस्तान और तटीय क्षेत्रों में है। हेन्सोल्ड्ट में जर्मन फेडरल सरकार की 25.1त्न हिस्सेदारी है। जर्मनी यूरोपियन यूनियन में भारत का सबसे बड़ा व्यवसायिक साझेदार है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इस सिस्टम के निर्माण के लिए यूपी स्थित इसके कोरबा डिविजन को चुना है। यह हेलीकॉप्टर ऑब्सटैकल अवॉयडेंस सिस्टम 1,000 मीटर से भी ज्यादा दूर की बाधाओं का पता लगाने में सक्षम है। पतले से पतले तार, केबल, पोल, टावर या भौगोलिक क्षेत्र का भी यह पता लगा लेता है। तारों के समांतर उड़ते समय भी यह उसे देख लेता है, जहां कई बार रडार भी फेल हो जाते हैं।

जेल रोड पर देर रात गुंडागर्दी

● राजा भोज परिसर में चाकू लिए 6 बदमाश घुसे, कार में की तोड़फोड़, सीसीटीवी वीडियो आया सामने

भोपाल (नप्र)। भोपाल के गांधीनगर क्षेत्र में मंगलवार देर रात बदमाशों ने गोंडीपुरा जेल रोड स्थित राजा भोज परिसर में जमकर उत्पात मचाया। करीब रात 2 बजे छह अज्ञात बदमाशों का गिरोह परिसर में घुसा और वहां खड़ी दो गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी। घटना के दौरान दो बदमाशों के हाथ में चाकू भी दिखाई दे रहे हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है।

पुलिस के अनुसार बदमाश बुलेट पर सवार होकर आए थे और लगातार बलेनो बलेनो चिल्ला रहे थे। उनके निशाने पर बलेनो कार थी, लेकिन जानकारी न होने के चलते उन्होंने सामने खड़ी अन्य गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। क्षतिग्रस्त वाहनों में महेश ठाकुर की कार भी शामिल है। घटना से पीड़ित लोगों ने बताया कि जिन बदमाशों ने हमला किया, उनका उनसे कोई संबंध नहीं है और न ही किसी तरह की रंजिश है। आरोपी पूरी तरह अज्ञात हैं और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए।

पुलिस की टीमें कर रहीं सर्चिंग

गांधीनगर थाना प्रभारी बृजेंद्र मर्सकोले ने बताया कि रात करीब 2 बजे छह अज्ञात युवक आए थे। उन्होंने गाड़ियों के कांच तोड़कर नुकसान पहुंचाया और चाकू लहराते हुए फरार हो गए। दो बदमाशों के हाथ में चाकू साफ दिखाई दे रहा है। पीड़ित पक्ष थाने पहुंच गया है। पुलिस की टीमें इलाके में लगातार सर्चिंग कर रही हैं, जल्द कार्रवाई की जाएगी।

कार से मिली 3.56 लाख की शराब

● आबकारी विभाग की कार्रवाई, कार छोड़ भाग निकला युवक

भोपाल (नप्र)। भोपाल में एक कार से 3 लाख 56 हजार रुपए की अवैध शराब जब्त की गई। कार्रवाई आबकारी विभाग ने बुधवार सुबह की। इस दौरान एक युवक कार छोड़कर भाग निकला।
आबकारी कंट्रोलर आरजी भदौरिया ने बताया कि बावड़िया कलां स्थित आकृति रिट्रीट कॉलोनी क्षेत्र में यह कार्रवाई कर 306 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई।

घेराबंदी कर की कार्रवाई

आबकारी विभाग की टीम ने कॉलोनी के पास घेराबंदी करते हुए एक कार को रोका। इसी दौरान चालक फरार हो गया। कार की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड हाई रेंज की अंग्रेजी शराब की 34 कार्टूनों में करीब 306 लीटर शराब भरी मिली। इस पर कार और शराब जब्त किए गए। अज्ञात आरोपी के विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क, 34(2) के तहत केस दर्ज किया गया।
लगातार कार्रवाई होगी– सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र धाकड़ ने बताया कि टीम द्वारा लगातार अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की जा रही है। आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।

सीएम का हेलिकॉप्टर बिना इंश्योरेंस के उड़ता रहा

18 अक्टूबर को खत्म हो चुका फ्रांस की कंपनी के हेलिकॉप्टर का इंश्योरेंस, दोबारा बुलाए टेंडर

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस समय बिना बीमा वाले हेलिकॉप्टर से उड़ रहे हैं। सीएम इस हेलिकॉप्टर से प्रदेश की राजधानी के अलावा अलग-अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। फ्रांस की कंपनी से खरीदे गए हेलिकॉप्टर के बीमा के लिए सरकार ने बीमा कंपनियों से 70 करोड़ रुपए के ऑफर मांगे थे, लेकिन कोई कंपनी आगे नहीं आई।

विमानन विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार शुक्ल ने मीडिया से कहा कि उन्हें हेलिकॉप्टर के बीमा खत्म होने की जानकारी नहीं है। इस मामले में विमानन विभाग के कमिश्नर चंद्रमौली शुक्ला ही अधिक स्पष्ट जानकारी दे सकते हैं।

बीमा न होने के बावजूद उड़ानें जारी– बताया जाता है कि 18 अक्टूबर से इस हेलिकॉप्टर का बीमा समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद सीएम, मंत्री और अधिकारियों की टीम इसमें दौरे कर रही है। अब 14 नवंबर को विमानन विभाग ने 27 नवंबर तक बीमा के लिए नया टेंडर जारी किया है।

बीमा कंपनियों के सामने रखी गई शर्तें– हेलिकॉप्टर का बीमा कराने के लिए सरकार ने कंपनियों के समक्ष शर्त रखी है कि किसी भी दुर्घटना, हाईजैक या आतंकी हमले की स्थिति में

नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। बीमा में फिजिकल लॉस या डैमेज, उड़ान, ऑपरेशन, टैक्सी सेवा या ग्राउंड कवरेज शामिल होंगे।

थर्ड पार्टी लायबिलिटी के अंतर्गत हेलिकॉप्टर की प्रॉपर्टी, पैसेंजर और क्रू लीगल लायबिलिटी बीमा में शामिल होगी। प्रस्तावित मूल्य दो करोड़ रुपए तय किया गया है। वर्तमान बीमा में हल ऑल रिस्क, हल वार रिस्क, थर्ड पार्टी, पैसेंजर और क्रू लायबिलिटी DGCA नियमों के अनुसार शामिल हैं।

2021 में हुई थी दुर्घटना

कोरोना काल में 6 मई 2021 को राज्य सरकार का प्लेन बिना बीमा के डैमेज हो गया था। यह विमान गुजरात से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर ग्वालियर आ रहा था। लैंडिंग के दौरान रनवे से करीब 300 फीट पहले लगे अरेस्टर बैरियर से टकराने के कारण विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। विमान का कॉकपिट और प्रोपेलर ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गए थे। यह दो इंजन वाला किंग एयर बी-250 (टर्बोप्रॉप) विमान था, जिसमें 9 यात्री और 2 पायलट बैठ सकते थे। मई 2021 तक इस विमान ने 210 घंटे 2 मिनट की उड़ानें पूरी की थीं।

कांग्रेस उठा चुकी है जेट विमान खरीदी पर सवाल– उधर, मोहन यादव सरकार द्वारा चैलेंजर 3500 जेट विमान की खरीदी को एक साल पहले मंजूरी दी जा चुकी है। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार रहे केके मिश्रा ने कहा कि 2021 में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का बीमा नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

स्वच्छता, जल संरक्षण में अच्छा काम, मिला इनाम

भोपाल में निगम ने सम्मान समारोह रखा, मंत्री-विधायक के हाथों मिला पुरस्कार

भोपाल (नप्र)। राजधानी भोपाल में स्वच्छता, जल स्त्रोतों के संरक्षण की दिशा में बेहतर काम करने वालों को बुधवार को इनाम मिला। मानस भवन में हुए कार्यक्रम में मंत्री, विधायक-महापौर ने पुरस्कार वितरित किए।

नगर निगम ने सम्मान समारोह आयोजित किया। मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवानदास सबनानी, महापौर मालती राय, एमआईसी मेंबर एवं बीजेपी जिलाध्यक्ष रविंद्र यती आदि ने स्वच्छता मित्रों और संस्थाओं को पुरस्कृत किया।

देश का दूसरा सबसे साफ शहर है भोपाल– भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश का दूसरा सबसे साफ शहर घोषित किया गया था। भोपाल ने इस बार तीन स्थान की छलांग लगाई और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में दूसरा स्थान हासिल किया।

भोपाल को 12,067 अंक, 7 स्टार रैंकिंग भी मिली– कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में भोपाल को 7 स्टार रैंकिंग भी मिली हुई है। वहीं, भोपाल ने देश की सबसे स्वच्छ तम राजधानी होने के साथ ही वाटर+ सिटी का गौरव भी बरकरार रखा है। रीड्यूज, रियूज, रिसायकल थीम पर हुए स्वच्छ सर्वेक्षण-2024 में भोपाल नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण में निर्धारित 10 हजार अंकों में से 9567 अंक और सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित 2500 अंकों में से पूरे अंक प्राप्त किए।

इस प्रकार 12 हजार 500 अंकों में से भोपाल शहर ने 12 हजार 067 अंक अर्जित करते हुए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दूसरा और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

अच्छा स्थान पाने पर स्वच्छता मित्रों का भी सम्मान

स्वच्छ सर्वेक्षण में अच्छा स्थान पाने पर स्वच्छता मित्रों का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम में एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल, राजेश हिंगोरानी, सुषमा बाविसा, जोन अध्यक्ष विमलेश ठाकुर, राजेश चौकसे, बृजुला सचान, आरती अनेजा, पार्षद वी. शक्ति राव, शिवलाल मकोरिया, कुसुम चतुर्वेदी आदि भी मौजूद थे।

हॉक फोर्स इंस्पेक्टर राजनांदगांव में शहीद

● नक्सलियों से हुई थी मुठभेड़, सीएम ने दी श्रद्धांजलि, दो बार मिल चुका था वीरता पुरुस्कार

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ सीमा पर राजनांदगांव के जंगलों में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में एमपी हॉक फोर्स के इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए हैं। आशीष शर्मा नरसिंहपुर जिले के बोहानी के रहने वाले हैं। 2016 बैच के प्लाटून कमांडर हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शर्मा को श्रद्धांजलि दी है।

मीडिया रिपार्ट्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ के बोरतलाव इलाके से सटे कंधुर्रा के जंगलों में गोलाबारी हो रही थी। इसी दौरान एमपी के इंस्पेक्टर को गोली लगी और वे शहीद हो गए। कंधुर्रा के जंगलों में नक्सलियों की एमपी-छत्तीसगढ़ के सुरक्षाबल की जॉइंट टीम नक्सल विरोधी ऑपरेशन पर निकली थी।

एमपी-महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर नक्सलियों के होने की सूचना मिलने के बाद ऑपरेशन शुरु किया गया। इस दौरान नक्सलियों से जैसे ही आमना-सामना हुआ दोनों तरफ से गोलाबारी शुरु हो गई। इस दौरान इंस्पेक्टर को गोली लगी। उन्हें डोंगरगढ़ अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

सीएम ने दी श्रद्धांजलि

सीएम डॉ. मोहन यादव ने आशीष शर्मा को X पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा- आज मप्र हॉक फोर्स के निरीक्षक आशीष शर्मा नक्सलियों से मुठभेड़ में वीरगति को प्राप्त हुए। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की संयुक्त टीम द्वारा छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के जंगलों में नक्सल विरोधी ऑपरेशन के दौरान उन्होंने अभूतपूर्व वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। नक्सल उन्मूलन के राष्ट्रीय अभियान में उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उन्हें पूर्व में कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी प्रदर्शित करने के लिए दो बार भारत सरकार द्वारा वीरता पदक से सम्मानित किया गया था।

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एसएसआर रिपोर्ट में फर्जीवाड़े के आरोप गहराए

भोपाल (नप्र)। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया पर उठे सवाल अब एक बड़े अकादमिक विवाद में बदल गए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एवीबीपी ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय ने ए++ ग्रेड हासिल करने के लिए एसएसआर रिपोर्ट में कई गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए हैं। मामले को गंभीर बताते हुए एवीबीपी ने तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को प्रमाण सौंपकर तत्काल एफआईआर दर्ज करने और विश्वविद्यालय में धारा 54 लागू करने की मांग की है। इस मुद्दे पर आज दोपहर होने वाली प्रेस वार्ता में एवीबीपी प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी नए तथ्य और दस्तावेज साझा करेंगे।
मंत्री से मुलाकात, एफआईआर और धारा 54 लागू करने की मांग– एवीबीपी प्रतिनिधिमंडल ने प्रांत मंत्री केतन चतुर्वेदी के नेतृत्व में तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की और स्स्क्ररिपोर्ट में कथित अनियमितताओं से जुड़े प्रमाण सौंपे। एवीबीपी ने कुलपति सहित संबंधित दोषियों पर तुरंत एफआईआर, परिसर में धारा 54 लागू करने और एनएएसी मूल्यांकन प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच कराने की मांग रखी है।

इंदौर से ओंकारेश्वर 25 मिनट में पहुंच सकेंगे

● 12 जगह के लिए हेलिकॉप्टर उड़ेंगे ● इंदौर-ओंकारेश्वर का किराया 2500 तो भोपाल से पचमढ़ी का 5 हजार रुपए तय

भोपाल । इंदौर से ओंकारेश्वर जाने में सिर्फ 25 और भोपाल से पचमढ़ी पहुंचने में 40 मिनट लगेंगे। मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग 8 बड़े शहर और 3 नेशनल पार्क के लिए हेलिकॉप्टर सेवा 20 नवंबर से शुरू कर रहा है।

इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी हो या कान्हा, बांधवगढ़-एसटीआर (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) और दोनों ज्योतिर्लिंग। पीएमश्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा की नियमित उड़ानें यहां के लिए रहेंगी। इंदौर-ओंकारेश्वर का किराया 2500 और भोपाल से पचमढ़ी का किराया 5 हजार रुपए तय किया गया है।

अंतरराज्यीय वायु सेवा वाला पहला स्टेट बनेगा– हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद एमपी देश में अंतरराज्यीय वायु सेवा संचालित करने वाला पहला स्टेट बन जाएगा। सप्ताह में 5 दिन हेलिकॉप्टर उड़ेंगे, जो 3 सेक्टर- वेलनेस, वाइल्ड लाइफ और धार्मिक स्थलों को जोड़ेंगे। अभी 4 बड़े शहर- भोपाल, इंदौर, उज्जैन-जबलपुर, 2 ज्योतिर्लिंग- महाकाल उज्जैन और ओंकारेश्वर खंडवा, 3 नेशनल पार्क- कान्हा, बांधवगढ़ और सतपुड़ा और 3 धार्मिक शहर- अमरकंटक, चित्रकूट-मैहर को जोड़ा गया है।

थोड़ा समय बचेगा, पर खर्च ज्यादा होगा– भोपाल से पचमढ़ी का किराया 5 हजार है। यदि भोपाल से पचमढ़ी कार से पहुंचा जाए तो एक फैमिली 5 हजार रुपए से कम खर्च में पहुंच जाएगी, जबकि हेलिकॉप्टर से एक फैमिली के 5 सदस्यों का किराया 25 हजार रुपए लगेगा। दूसरी ओर, हेलिकॉप्टर से पचमढ़ी पहुंचने में औसत समय ढाई से तीन घंटे आएगा। इसमें घर से एयरपोर्ट, फिर चेक इन और आउट, उड़ान का समय भी शामिल हैं। अब बचे दो से ढाई घंटे के लिए पांच सदस्यों की एक फैमिली पर 20 हजार रुपए का खर्च बढ़ेगा। हालांकि, जिम्मेदार हेलिकॉप्टर को लेकर अच्छा रिस्पांस मिलने की बात कह रहे हैं।

सेक्टर-1: इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच उड़ान

इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधीसागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतिया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा शामिल हैं। यानी, मालवा-निमाड़ का बेल्ट शामिल रहेगा। पहले फेज में इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेलिकॉप्टर की सप्ताह में 5 दिन नियमित उड़ान रहेगी। सबसे कम किराया 5 हजार तो सबसे ज्यादा साढ़े 6 हजार रुपए है।

इन पांच दिन सेवा होगी

● सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार और मंगलवार। ● 2 दिन- बुधवार और गुरुवार को कोई उड़ान नहीं रहेंगी।

सुविधा मिलेगी, लेकिन प्रोसेस लंबी होगी

पीएमश्री पर्यटन हेलिकॉप्टर सेवा में एक बड़ा दावा किया जा रहा है कि कम समय पर सीधे स्पॉट तक लोग जा सकेंगे, लेकिन यदि टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रोसेस लंबी है। बात भोपाल की करें तो गांधीनगर में एयरपोर्ट है। ऐसे में शहरी क्षेत्र के पर्यटक को एयरपोर्ट पहुंचने में ही 30 से 40 मिनट लग जाते हैं। फिर चेक इन की प्रोसेस। ऐसे में 2 से 3 घंटे का वक्त लगेगा।

तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत

● रायसेन से लौट रहे थे पति-पत्नी और बेटा, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ट्रक चालक

भोपाल (नप्र)। भोपाल के बिलखिरिया क्षेत्र में मंगलवार दोपहर हुए सड़क हादसे में बाइक सवार बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। जबकि उसके पति और बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को पकड़ लिया है। मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया और घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है।

रातीबड़ की रहने वाली थी महिला

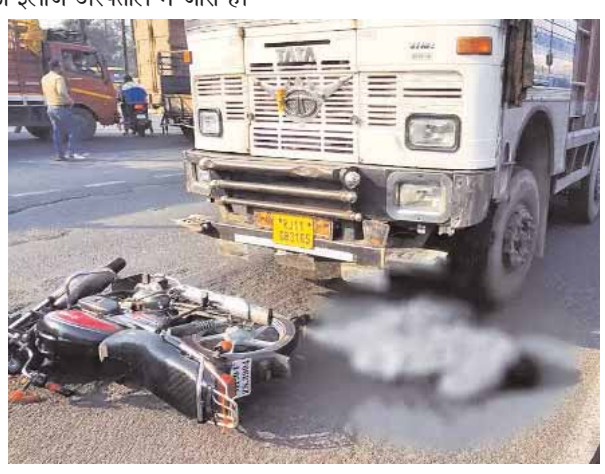

जानकारी के अनुसार मृतका ममता बाई (65), पत्नी सवाई सिंह, ग्राम सेमरी, थाना रातीबड़ की निवासी थीं। वह रायसेन में रहने वाले एक रिश्तेदार के यहां गमी में शामिल होने गई थीं। मंगलवार दोपहर ममता बाई अपने पति सवाई सिंह और बेटे वीरेंद्र सिंह के साथ बाइक से भोपाल लौट रही थीं।

जैसे ही तीनों बिलखिरिया थाना क्षेत्र के बायपास चौराहे के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ममता बाई को मृत घोषित कर दिया। इधर, हादसे के बाद मौके से फरार हुए ट्रक चालक को पुलिस ने कुछ ही घंटों में तलाश कर पकड़ लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और वाहन को जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

संपादकीय

शेख हसीना-प्रायोजित मृत्यु दंड

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मानवता के खिलाफ अपराध करने का दोषी ठहराकर सजा ए मौत सुनाई है। पिछले साल जुलाई में बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ भड़के छात्र विद्रोह में पुलिस व सेना की कार्रवाई में 1400 लोग मारे गए थे। इसका दोष वहां की अंतरिम मोहम्मद युनूस सरकार ने शेख हसीना पर मढ़ते हुए उन्हें सजा देने के लिए भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। हालांकि भारत इसे मानेगा, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। क्योंकि शेख हसीना भारत की पक्की दोस्त रही हैं और भारत अपने मित्रों को कभी धोखा नहीं देता। शेख हसीना को जिस तरह मौत की सजा सुनाई गई है, उसकी आशंका पहले से ही थी। क्योंकि यह प्रायोजित और नैसर्गिक न्याय के खिलाफ चलाया गया मुकदमा था। इसमें शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका ही नहीं दिया गया। इक तरफ सबूतों और गवाहियों के आधार पर मृत्यु दंड सुना दिया गया। फैसले के मुताबिक हसीना को 30 दिन के भीतर सरेंडर करना होगा। साथ ही उनके पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को भी मौत की सजा सुनाई गई है। फैसले में अवामी लीग के इस नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया गया। खुद शेख हसीना ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने भी इस फैसले को अमान्य कर दिया है। खास बात यह है कि शेख हसीना को सजा सुनाने वाली अदालत खुद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण कहती है, जिसकी स्थापना 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान हुई थी। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने सोमवार को अपनी दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में साफ कहा कि संयुक्त राष्ट्र हर हाल में मौत की सजा के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने भी मामले की निष्पक्ष सुनवाई की बात कही थी। वैसे भी अब यह साफ हो चुका है कि शेख हसीना के खिलाफ जो कथित छात्र आंदोलन खड़ा किया गया था, वह कट्टरपंथियों द्वारा हसीना को हटाने की छुपी चाल थी। अब सवाल यह है कि क्या भारत बांग्लादेश की हसीना के प्रत्यर्पण की बात मानेगा? इसकी संभावना न्यूनतम है। शेख हसीना के पास बांग्लादेश की कोर्ट में 17 दिसंबर 2025 तक सरेंडर कर अपील करने का कानूनी विकल्प उपलब्ध है। हसीना फैसले के खिलाफ तब तक अपील नहीं कर सकती जब तक कि वह फैसले के 30 दिनों के भीतर सरेंडर नहीं कर देती या गिरफ्तार नहीं हो जाती। यानी उनके पास इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश के इस फैसले को चुनौती देने के लिए 17 दिसंबर 2025 तक का ही वक्त है। यदि शेख हसीना इस तारीख तक बांग्लादेश की किसी कोर्ट में सरेंडर नहीं करतीं या गिरफ्तारी नहीं देती हैं, तो अपील का कानूनी अधिकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। उनके पास दूसरा विकल्प यह है कि वो भारत में ही रहें और भारत सरकार से उम्मीद करें कि वो उन्हें किसी हाल में बांग्लादेश को न सौंपे। असदुज्जमां खान भी भारत में ही हैं। हालांकि दोनो देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि है। लेकिन इसमें कुछ पतली गलियां भी हैं, जिनके आधार पर भारत सरकार हसीना को सौंपने से इंकार कर सकती है। उधर बांग्लादेश में इस फैसले का व्यापक विरोध हो रहा है। युनूस सरकार ने शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया है। कुल मिलाकर हालात और खराब होने का अंदेशा है। परिस्थितियां गृह युद्ध भड़कने की ओर इशारा कर रही हैं। भारत को भी सतर्क रहना होगा।

एग्जिट पोल- डेटा, धारणा और लोकतंत्र का वैज्ञानिक चेहरा

बिहार का 2025 का विधानसभा चुनाव एक बड़ी सीख देता है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीति की समझ पर नहीं चलता, बल्कि यह डेटा, सांख्यिकी, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धतियों पर भी आधारित है। एग्ज़िट पोल कोई जादू नहीं हैं; वह तो हजारों वोटरों के व्यवहार, सामाजिक पैटर्न, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और सांख्यिकीय विश्लेषण का संयुक्त परिणाम होते हैं। वे 100 फीसदी शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि, समाज और मनुष्य दोनों गतिशील हैं।

नजरिया

अजित लाड

वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के आधिकारिक नतीजों ने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया। इस बार एग्जिट पोल्स ने लगभग वही रुझान दिखाए, जो अंततः मतगणना में सामने आया। यह वही बिहार है, जहां 2015 के चुनाव में अधिकांश एग्ज़िट पोल बुरी तरह चूक गए थे और 2020 में भी कई अनुमानों ने विचलन दिखाया था। लेकिन, 2025 के चुनाव ने यह भरोसा मजबूत किया कि यदि सैंपलिंग वैज्ञानिक, बूथ चयन सटीक और जनसांख्यिकीय विश्लेषण गहरा हो, तो एग्ज़िट पोल महज अनुमान नहीं, बल्कि एक विश्वसनीय शोध-संकेतक बन सकते हैं।

सबसे पहले बात कामख्या एनालिटिक्स की। इस एजेंसी ने एनडीए के लिए 167-187 सीटों की रेंज दी थी और अंतिम नतीजे जब इसी के आसपास ठहर गए। इससे साफ हो गया कि इसकी सैंपलिंग रणनीति सबसे अधिक सटीक साबित हुई। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय-सामाजिक जटिलताएं बहुत गहरी हैं, इस स्तर की भविष्यवाणी आसान नहीं होती। इसका अर्थ है कि कामाख्या ने बूथ चयन, जातिगत वेटेज और क्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन इतनी बारीकी से किया कि जमीनी संकेत सही पैमाने में कैप्चर हो गए।

मेट्राइज़ (147-167) और टुडेज़ चाणक्य (148-172) ने भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत में दिखाया था और वास्तविक नतीजों ने उनके अनुमानों को लगभग पूरी तरह सही साबित किया। विशेषकर चाणक्य की मॉडलिंग जो पिछले कुछ वर्षों में अपनी उच्च सटीकता के लिए पहचानी जाती है, एक बार फिर भरोसेमंद निकली। महागठबंधन के लिए कामाख्या (54-74), मेट्राइज़ (70-90) और चाणक्य (65-89) द्वारा दी गई रेंज भी परिणामों से काफी मेल खाती रही। जो बताती है कि इन एजेंसियों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ताकत का संतुलित आकलन किया था। छोटे दलों की भविष्यवाणी करना आमतौर पर सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि उनका वोट बिखरा हुआ होता है और उनका प्रभाव क्षेत्र-विशेष तक सीमित रहता है। लेकिन, इस बार यहाँ भी सटीकता उल्लेखनीय रही। उदाहरण के तौर पर मेट्राइज़ ने जेएसपी/जेएसयूपी को ठीक 5 सीटें दी। जबकि, एक्सिस माय इंडिया ने 0-2 सीटों की संभावना जताई थी और चुनाव परिणाम इन्हीं अनुमानों के आस-पास रहे। पीपुल्स पल्स ने एनडीए के लिए 133-159 और महागठबंधन के लिए 75-101 का व्यापक रेंज दिया था, फिर भी उसका आकलन अंतिम ट्रेंड की दिशा के बिल्कुल अनुरूप रहा। इसी तरह भास्कर एग्जिट पोल (145-160 / 73-91) भी बिना किसी बड़े विचलन के, राजनीतिक हवा को पढ़ने में सफल रहा।

अन्य एजेंसियां जैसे पी-मार्क, पोल स्टार्ट और पीपुल्स इनसाइट ने भले ही अपेक्षाकृत व्यापक रेंज दी हो, लेकिन इन सभी का सामूहिक संकेत एक ही दिशा में था एनडीए की बढ़त। जब अलग-अलग स्थानों पर काम कर रही टीमें, अलग-अलग मॉडलिंग पद्धतियों, सैंपलिंग फ्रेम्स और डेटा-संग्रह तकनीकों के बावजूद एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, तो यह किसी भी चुनाव विश्लेषण के लिए 'डेटा-संगति' का मजबूत प्रमाण होता है। इस बार लगभग सभी प्रमुख एजेंसियों ने बूथ कवरेज का विस्तार किया, डेमोग्राफिक मैपिंग को सूक्ष्म रखा, वोटर प्रोफाइलिंग को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया और सैंपलिंग विधि को पिछले चुनावों की तुलना में कहीं अधिक परिशुद्ध बनाया। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ स्थानीय मुद्दे, जातीय समीकरण और क्षेत्रीय प्राथमिकताएँ लगातार बदलती रहती हैं, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी का परिणाम है कि अधिकांश एग्ज़िट पोल असली नतीजों के बेहद करीब उतर आए।

चुनावी परिणामों के बाद एक और तथ्य सामने आया कुछ राजनीतिक हलकों में जिस 'फेक एग्ज़िट पोल' का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई थी, वह इस बार पूरी तरह धराशायी हो गया। सामूहिक सटीकता इतनी प्रबल थी कि किसी भी तरह के आरोप स्वतः ही निरर्थक साबित हो गए। जनता ने भी देखा कि इस बार एग्ज़िट पोल न वास्तविकता से दूर थे, न किसी एकतरफ़ा झुकाव वाले प्रतीत हुए। 2025 का यह चुनाव एक बड़ी सीख छोड़ता है। लोकतंत्र सिर्फ राजनीति की समझ पर नहीं चलता, बल्कि डेटा, सांख्यिकी, समाजशास्त्र और वैज्ञानिक पद्धतियों पर भी आधारित है। एग्ज़िट पोल कोई जादू नहीं हैं; वे हजारों वोटरों के व्यवहार, सामाजिक पैटर्न, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों और सांख्यिकीय विश्लेषण का संयुक्त परिणाम होते हैं। वे 100 फीसदी शुद्ध नहीं हो सकते। क्योंकि, समाज और मनुष्य दोनों गतिशील हैं।

यदि सर्वेक्षण ईमानदार हों, सैंपलिंग वैज्ञानिक हो और डेटा वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता हो, तो एग्ज़िट पोल ज़रूर चुनावी माहौल का विश्वसनीय संकेतक बनते हैं। बिहार चुनाव 2025 ने इस तथ्य को सबसे सशक्त रूप में सिद्ध किया है। यह चुनाव न केवल राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि चुनाव-अध्ययन और डेटा-विश्लेषण की दुनिया के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। यह संदेश स्पष्ट है वैज्ञानिक दृष्टि, पारदर्शी डेटा और सटीक मॉडलिंग लोकतंत्र को अधिक मजबूत और विश्वसनीय बनाती है। एग्ज़िट पोल इस बार सिर्फ अनुमान नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक समझ का एक वैज्ञानिक दर्पण बनकर उभरे हैं और यह निस्संदेह एक सुखद और प्रेरक संकेत है।

अमेज़न को कौन कर रहा है बर्बाद?

जलवायु सम्मेलन

कुमार सिद्धार्थ

लेखक पिछले चार दशक से पत्रकारिता और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

दुनिया के सबसे विशाल वर्षावन अमेज़न पर खतरा अब किसी दूर की आशंका नहीं, बल्कि एक निकट आती सच्चाई है। वनों की अंधाधुंध कटाई, तेल और गैस के उत्खनन तथा जलवायु परिवर्तन ने इसे उस बिंदु तक पहुँचा दिया है जहाँ से लौटना शायद संभव नहीं रहेगा। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अमेज़न अब 'कार्बन सोखने वाले' वन से 'कार्बन छोड़ने वाले' क्षेत्र में बदलने की कगार पर है।

ऐसे समय में जब संयुक्त राष्ट्र का जलवायु सम्मेलन सीओपी-30 ब्राज़ील के बेलें शहर में चल रहा है, एक नई रिपोर्ट ने उस वित्तीय ढाँचे को बेनकाब किया है जो अमेज़न के विनाश की जड़ों में छिपा है।

पर्यावरण संगठन स्टैंड.अर्थ की रिपोर्ट 'बैंक्स वर्सेस द अमेज़न स्कोरकार्ड' बताती है कि 2016 में पेरिस समझौते के बाद से अमेज़न क्षेत्र में तेल और गैस परियोजनाओं को मिलने वाले वित्त का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सिर्फ दस बैंकों से आता रहा है। इनमें जेपी मॉर्गन चेज़, सिटी, बैंक ऑफ अमेरिका, इताउ यूनिबैंको (ब्राज़ील) और एचएसबीसी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन बैंकों ने अमेज़न के भीतर जीवाश्म ईंधन से जुड़ी परियोजनाओं में 15 अरब डॉलर से अधिक झोंक दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में यूरोप के कई बैंकों ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। फ्रांस का बीएनपी परिबा और ब्रिटेन का एचएसबीसी अब अमेज़न से जुड़ी कंपनियों को ऋण देना बंद कर चुके हैं। उन्होंने ऐसी नीतियाँ अपनाई हैं जो अमेज़न में तेल और गैस उत्खनन करने वाली कंपनियों को वित्त नहीं देतीं।

लेकिन जहाँ यूरोपीय बैंक पीछे हटे, वहीं अमेरिका और लैटिन अमेरिका के बैंक उस खाली जगह को भरने में लगे हैं। ब्राज़ील का इताउ यूनिबैंको अब शीर्ष पर पहुँच गया है — सिर्फ पिछले 18 महीनों में उसने 378 मिलियन डॉलर की नई फंडिंग दी है। जेपी मॉर्गन चेज़ और बैंक ऑफ अमेरिका उससे थोड़ा पीछे हैं। इसी अवधि में पेरू के क्रेडिकॉर्प और कनाडा के स्कोटियाबैंक ने भी अपने निवेश को लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है।रिपोर्ट की प्रमुख शोधकर्ता डॉ. देवयानी सिंह का कहना है कि यूरोपीय बैंकों ने अपेक्षाकृत सख्त नीतियाँ लागू की हैं, लेकिन कोई भी बैंक अब तक अपने वित्तपोषण को शून्य नहीं कर पाया। हर बैंक को लूप होल बंद करने होंगे और बिना देरी अमेज़न से बाहर निकलना होगा।

द इकोलॉजिस्ट में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, अमेज़न में तेल और गैस की खुदाई सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन को भी गहराई से प्रभावित कर रही है। ब्राज़ील, इक्वाडोर, पेरू और कोलंबिया में 6,000 से अधिक तेल-दूषित स्थल दर्ज किए गए हैं। उत्खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले समुदायों में कैंसर, गर्भपात और श्वसन रोगों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद, सरकारें पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्राज़ील ने इस साल की शुरुआत में 68 नए तेल ब्लॉक की नीलामी की। इक्वाडोर में यासुनी नेशनल पार्क में ड्रिलिंग रोकने के लिए 2023 में हुए जनमत-संग्रह के बाद भी काम जारी है। पेरू में 31 नए तेल ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिनमें से कई 400 से अधिक स्वदेशी समुदायों की भूमि से ओवरलैप करते हैं।

अमेज़न की ओलिविया बिसा कहती हैं, जब जंगल खुद संकट में है, तब बैंक ऑफ अमेरिका, स्कोटियाबैंक और इताउ जैसे बैंक इन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। दशकों से हमारे समुदाय इस विनाश का सबसे बड़ा भार उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि बैंक अमेज़न को तेल की लत से मुक्त करें। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2024 से अब तक अमेज़न क्षेत्र में 2 अरब डॉलर से अधिक की नई फंडिंग केवल छह कंपनियों को मिली है- पेट्रोब्रास, एनेवा, गनवोर, ग्रैन टिएरा, प्लसपेट्रोल कैमिसेआ और हंट ऑयल पेरू। इन सभी पर भ्रष्टाचार, पर्यावरणीय क्षति और स्वदेशी अधिकारों के उल्लंघन के आरोप हैं।

ब्राज़ील की कंपनी एनेवा को हाल ही में संघीय अदालत ने अपनी गतिविधियाँ रोकने का आदेश दिया था क्योंकि उसने स्वदेशी समुदायों के अधिकारों और पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन किया था। फिर भी, उसे इताउ यूनिबैंकों, बैंकों डो ब्रासिल, सैंटेंडर और अन्य बैंकों से वित्त मिलता रहा।

इसी तरह, स्विस कंपनी गनवोर को 2013 से 2020 के बीच इक्वाडोर में अधिकारियों को रिश्वत देकर तेल अनुबंध हासिल करने का दोषी पाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसे आईएनजी बैंक से वित्तीय सहायता मिलती रही। इससे यह साफ़ होता है कि आंशिक प्रतिबंध और 'प्रोजेक्ट-लेवल' नीतियाँ अक्सर औपचारिकता से ज़्यादा कुछ नहीं होतीं। रिपोर्ट में सभी बैंकों से अपील की गई है कि वे 2030 तक अमेज़न में तेल और गैस परियोजनाओं के वित्तपोषण को पूरी तरह समाप्त करें - चाहे वह ऋण के रूप में हो, बॉन्ड में निवेश के रूप में या परामर्श सेवाओं के रूप में। साथ ही, उन्हें संयुक्त राष्ट्र की स्वदेशी अधिकारों पर घोषणा (NDRIP) के अनुरूप नीतियाँ अपनाने की सिफारिश की गई है।

स्टैंड.अर्थ की वरिष्ठ अभियानकर्ता मार्टीना डोमिनियाक कहती हैं, कॉप-30 सम्मेलन बैंकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि वे अमेज़न में जीवाश्म ईंधनों के वित्तपोषण को बंद करने की ठोस घोषणा करें। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि जीवन के अधिकार का सवाल है।

आज अमेज़न वह साँस है जिससे पृथ्वी जीवित है। पर यदि यह साँस रुक गई, तो इसका असर पूरे ग्रह पर पड़ेगा। आने वाला दशक तय करेगा कि यह महान वन जीवित रहेगा या इतिहास बन जाएगा। कॉप-30 सम्मेलन के दौरान यह सवाल सिर्फ सरकारों या पर्यावरणविदों के लिए नहीं, बल्कि उन बैंकों के लिए भी है जिनके धन से यह विनाश चल रहा है। अगर उन्होंने दिशा बदली, तो बेलें में चल रहा यह सम्मेलन अमेज़न को बचाने की नई शुरुआत कर सकता है। और अगर नहीं, तो यह सभ्यता की सबसे हरी विरासत को खो देने की औपचारिक घोषणा होगी।

बिहार की औरतों को क्यों दोष दिया जा रहा?

विधानसभा चुनाव 2025

डॉ. तेजी ईशा

लेखक एसजीटी यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हैं।

बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया। रिजल्ट में एनडीए को बहुमत मिला, फिर से नीतीश सरकार के बनने का रास्ता साफ हुआ। ये फैसला बिहार की जनता का था। स्त्री-पुरुष दोनों मतदाताओं का था। अगर बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम देखेंगे तो सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष कहीं टिका ही नहीं। एक तरफा चुनाव था, ये परिणाम से साफ हुआ। लेकिन इस बार महिला मतदाताओं ने बढ़चढ़ कर वोट किया। बिहार में महिला मतदाताओं के वोट प्रतिशत आज ही नहीं बढ़े हैं। वर्ष 2005 के बाद से हर चुनाव में महिलाओं मे वोटिंग में आगे बढ़ के हिस्सा लिया है। इस मामले में कोरोना काल में हुए चुनाव अपवाद हो सकते हैं। फिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए महिलाओं को लालची बताया जा रहा? उन्हें तरह-तरह से बिकाऊ बोला जा रहा? दस हजार के लिए पलायन और बेरोजगारी खत्म न करने वाला बताया जा रहा?

असल में चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत राज्य के उन महिलाओं के खाते में दस हजार रुपये डाले जो जीविका समूह से जुड़ी हुई थीं। विपक्षी नेताओं को, कई जानकारों को और कई पत्रकारों को लगता है कि केवल इसी वजह से नीतीश सरकार या एनडीए को महिलाओं का वोट मिला। जबकि ये सरासर गलत बात है। आप कह सकते हैं कि इस योजना ने महिलाओं को सरकार के पक्ष में वोट करने का एक और कारण दे दिया लेकिन केवल दस हजार रुपए मिलने की वजह से महिलाओं ने वोट किया, ये गलत है। सरासर गलत है।

नीतीश कुमार जब पहली दफा राज्य के मुखिया बने तभी से उन्होंने महिला मतदाताओं को ध्यान में रख ये योजनाएं चलाईं। 2008 में नीतीश कुमार ने हाई स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दिलाया था। देखते-देखते गाँव-देहात की फिजा बदल गई थी। स्कूली ड्रेस पहने लड़कियां झुंड में साइकिल से स्कूल जाने लगीं। जब लड़कियां बाहर निकलीं तो कुछ शोहदे उनको परेशान करने लगे। नीतीश कुमार ने बिना 'एनकाउंटर' किए लड़कियों को भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई परेशान करेगा तो पुलिस उसका इलाज करेगी। फिर पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण। बिहार पुलिस में लड़कियों के लिए आरक्षण का इंतजाम इस मुख्यमंत्री ने किया।

शराब पीकर जब घर के मर्द नाटक करने लगे। घर की बेटी-पत्नी को मारने-पीटने लगे तो नीतीश ने शराबबंदी जैसा सख्त कदम उठाया। राज्य सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ लेकिन उन्होंने वो फैसला वापिस नहीं लिया। इससे भी राज्य की महिलाओं में एक भरोसा जगा। और इन सभी वजहों से हर विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने नीतीश का समर्थन किया। कम या जायदा। इस चुनाव में तो एक नई पार्टी भी थी। वो पार्टी कह रही थी कि हम चुनाव जीते तो सबसे पहले शराबबंदी खत्म करेंगे। उस पार्टी और उस दल के मुखिया ने ये भी नहीं सोचा कि एक बार महिलाओं से राय ले लें। उनसे पूछ लें। समझ लें। इससे उलट नीतीश कुमार ने अपने पूरे टर्म में। बीस साल के शासनकाल में महिलाओं को आगे रखा। अपने शुरुआती समय में नियमित तौर से महिलाओं की पंचायतें बिठाते थे और उसमें खुद जाते थे। वहाँ घंटों बैठ के महिलाओं की बातें सुनते थे।

मेरे कहने का मतलब कि नीतीश सरकार ने अपनी शुरुआती दिनों से राज्य की महिलाओं को एक अलग वोट के तौर पर देखा है। उन्होंने लड़कियों को 'जहां परिवार कहेगा वहीं वोट डालने की मशीन' नहीं माना। और इस वजह से राज्य की महिलाएं हर चुनाव में नीतीश में अपना भरोसा जताती रहीं हैं। इसलिए ये कहना बंद कर देना चाहिए कि महिलाओं ने कुछ पैसे के लालच में अपना वोट बेच दिया। उन्होंने नीतीश को वोट दिया क्योंकि नीतीश ने उन्हें पुरुषों से अलग समझा। उनकी आवाज। उनकी जरूरतों को समझा। उसके मुताबिक सरकार के नियम बनाए। सरकारी योजनाओं में महिलाओं को उनका हिस्सा दिलवाया।

और अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि महिलाएं दस हजार के चक्कर में बिक गईं तो राज्य के पुरुष तो सालों से शराब और एक समय के खाने के लिए बिकते रहे हैं। तब तो कोई पुरुषों को निशाना नहीं बनाता फिरता था। एक बार आखिर में कह दूँ, अगर राज्य के नेता और विपक्षी पार्टियां ये मान के आज बैठ गईं कि नीतीश सरकार को महिलाओं ने वोट केवल दस हजार रुपये के चक्कर में दिया है तो यकीन मानिए, आज से पाँच साल बाद होने वाले वाला चुनाव भी वो हार चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव में उनकी हार के असल वजह वो खोज ही नहीं पाए। और अगर सही वजह ही नहीं खोज पाए तो उसे ठीक क्या खाक करेंगे!

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

जवाहर चौधरी

लेखक व्यंग्यकार हैं।

गोपीचंद बॉडी सप्लायर

इधर साहित्य के इलाके में बादल बहुत घुमड़ रहे हैं। दिन दिन भर अंधेरा छाया रहता है, रात रात भर चांद-तारे गायब रहते हैं। जितने भी लोग बादल देखते हैं उनमें से आधे दन्न से कवि हो जाते हैं। बचे हुए में से आधे लघुकथाकार और बाकी से व्यंग्यकार, कथाकार, निबंधकार वगैरह पैदा होते हैं। उम्मीद तो रहती है कि बादल से पानी बरसेगा लेकिन टपकते हैं साहित्यकार और कुछ परजीवीनुमा भी आ जाते हैं मैदान में। अब आए हैं तो गीला भी होगा, कुछ कीचड़ भी और कुछ नाले -नदी, तालाब में भी पहुंचेंगे। भाई पानी तो पानी है, जिधर ढलान मिलेगी वह चल पड़ेगा। इसमें कोई रोक तो है नहीं।

इस झरते बरसते मौसम में साहित्य की सेवा यदि कोई कर रहा है तो वह प्रकाशक है। आप साहेबान दनादन लिखिए हम धड़ाधड़ छापेंगे। बस हो गया काम, आपका भी और हमारा भी। क्यों लिखना है, किसके लिए लिखना है, पाठक क्या होता है, क्या चाहता है इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल कोई कमबख्त करे तो उसे मौका मिलते ही सूखे कुवें में डाल दो। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वो भुगतना ही पड़ता है। पाठक लोग कोई दूसरी दुनिया के नहीं हैं। साहित्य सेवा के लिए प्रकाशक बेचारे को खूब सारे गीले-सूखे शब्द चाहिए जिन्हें वह किताब में बदल सकें। लेखक और प्रकाशक राजस्थानी समधी की तरह होते हैं। खूब गले मिलते हैं लेकिन रियायत जरा भी नहीं करते हैं। मजे की बात यह है कि यह गलाकाट रिश्ता एक बार बनता है तो जीवन भर के लिए बन जाता है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। याद दिला दें कि पुस्तक प्रकाशन के बाद भी पाठक की किसी को याद नहीं आती है। अब अगर पुस्तक का विमोचन नहीं हो तो मतलब क्या है साहित्य सेवा का!! लिखी, छपी, हाथ में आ गई, अब इसका कुछ तो करना पड़ेगा। विमोचन के अलावा और किया भी क्या जा सकता है। किसी आयोजन वैज्ञानिक को साथ में ले लो तो सब काम आसान हो जाता है। मतलब अतिथि, मुख्य अतिथि वगैरह वही फिट करवा देता है।

हॉल, फोटोग्राफर, प्रेस रिपोर्टर और खाने-पीने का बढ़िया इंतजाम आपकी जेब को ही करना है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है आयोजन में लोगों की उपस्थिति को लेकर। लोग आते नहीं हैं आजकल, जाहिल कहीं के। चाय-समोसा खिलाओ तो भी हॉल नहीं भर पाता है। लेखक को मजबूरन गोपीचंद बॉडी सप्लायर के पास जाना पड़ता है।

गोपीचंद हर मौके के लिए 'बॉडी' सप्लाई करता है। चाहे शादी हो, बारात, उठावना या पुस्तक विमोचन। वह सजी-धजी, धोई-धुलाई बॉडीज भेजता है। पॉलिश किए जूते, इस्तरीदार कपड़े और चेहरे पर साहित्यिक गहराई का भाव अलग से। विमोचन कार्यक्रम थोड़ा बोरिंग होता है, इसलिए बीच-बीच में तालियाँ भी बजानी पड़ती हैं, मौके बेमौके वाह वाह भी करना पड़ती है। यही कारण है कि इस प्रजाति की बॉडी थोड़ी महँगी मिलती है। लेकिन भैया, जब साहित्य में सिर दे ही दिया है तो सस्ता महंगा क्या देखना! अगले दिन अखबार में इस खबर के साथ फोटो छपेगी - 'लेखक महोदय का गरिमामय विमोचन समारोह संपन्न।' तो फटाक से फेमस भी तो हो जाओगे। किताबों को तो कहीं जाना नहीं है, अपने घर में ही पड़ी रहेंगी। तो भाई लोगों आगे-पीछे मत देखो.... चले चलो, बढ़े चलो।

दृष्टिकोण

सत्यप्रकाश नायक

लेखक जेंडर समानता के मुद्दे पर कार्य करते है।

क्या हमारी भाषा में बेटियों को बराबरी और सम्मान मिलता है?

शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे धारणाएँ गढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं छात्रों को निर्देश दिया गया, तो सामान्यत : माना जाता है कि इसमें सभी बच्चे शामिल हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता, तो 'छात्रा' शब्द की आवश्यकता क्यों होती? इसी तरह कक्षा में रोज सुनी जाने वाली आवाजें कौन करेगा?, कौन लाएगा?, कौन जाकर बोर्ड साफ़ करेगा? हमेशा पुल्लिंग में होती हैं। कक्षा में बैठी लड़कियाँ अनजाने ही इन वाक्यों से बाहर रह जाती हैं। यदि शिक्षक कहते कौन करेगा या करेगी? तो भाषा में ही बराबरी की खिड़की खुल जाती।

हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की शानदार जीत ने पूरे देश में उत्साह का माहौल बना दिया। टीवी चैनलों पर हेडलाइन दिखाई देती रहीं 'भारत की बेटियाँ चमकीं', 'बेटियों ने रचा इतिहास', 'टीम इंडिया की शेरनियों ने दिल जीता।' सोशल मीडिया पर गर्व से भरी पोस्टों की बाढ़ आ गई। देशभर के लोग बेटियों की उपलब्धि पर न केवल खुश हुए, बल्कि भावुक होकर बोले 'हमारी बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं।' यह दृश्य दिल को छू लेने वाला था।

लेकिन इस जश्न के बीच एक विचार भी मन में उठता है क्या हमारे समाज और हमारी भाषा में बेटियों को हमेशा यही बराबरी और सम्मान मिलता है? क्या हमारी रोज़मर्रा की भाषा उतने ही सहज रूप से बेटियों के पक्ष में खड़ी होती है जितना कि एक बड़ी जीत के बाद दिखाई देती है?

इसी सवाल से यह चर्चा शुरू होती है। 'बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रही हो!' यह वाक्य हमारे समाज और शिक्षा व्यवस्था में लगभग हर दिन सुनाई देता है। बच्ची जब कोई अच्छा काम करती है, तो शिक्षक, अभिभावक या रिश्तेदार उसे प्रोत्साहित करते हुए अक्सर 'बेटा' कहकर सराहते हैं। यह सुनने में सामान्य लगता है, क्योंकि हमारे सामाजिक परिवेश में 'बेटा' शब्द सफलता और उत्कृष्टता का मानक बन चुका है।

लेकिन क्या कभी किसी लड़के से कहा गया है बेटी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो? शायद ही कभी। और यदि कहा भी गया हो, तो लोग इसे मज़ाक में टाल देते हैं। यही हमारी भाषा में गहरे छिपा हुआ जेंडर है जो सुनाई तो देता है, पर चुभता नहीं।

भाषा और समाज का रिश्ता बहुत गहरा है। हमारी सोच, दृष्टि और संस्कारों को गढ़ने में भाषा की भूमिका निर्णायक होती है। हम जो बोलते हैं, वही हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है, और वही बच्चों की सोच का हिस्सा बन जाता है। जब भाषा में असमानता छिपी होती है, तो वह बच्चों की आत्म-छवि और आत्मविश्वास को भी असमान बना देती है।

बचपन में बच्चे अपने बारे में वही मानने लगते हैं जो वे बार-बार सुनते हैं। यदि किसी बच्ची को सराहने के लिए भी 'बेटा' कहना ज़रूरी समझा जाता है, तो इसका संदेश यही है कि उत्कृष्टता, साहस या नेतृत्व लड़का होने के गुण हैं। इससे अनजाने में बच्ची को यह महसूस होने लगता है कि 'बेटी' होना पर्याप्त नहीं है; उसे मूल्यवान बनने के लिए 'बेटा' कहलाना होगा। दूसरी ओर लड़के को 'बेटी' कहकर सराहना लगभग असंभव है, और यदि कोई ऐसा कर भी दे तो लोग इसे हँसी-ठिठोली में बदल देते हैं। यही भेद भाव बच्चों की पहचान और आत्मविश्वास पर गहरा असर छोड़ता है।

शब्द केवल वाक्य नहीं होते, वे धारणाएँ गढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम कहते हैं छात्रों को निर्देश दिया गया, तो सामान्यत: माना जाता है कि इसमें सभी बच्चे शामिल हैं। लेकिन अगर ऐसा ही होता, तो 'छात्रा' शब्द की आवश्यकता क्यों होती? इसी तरह कक्षा में रोज सुनी जाने वाली आवाजें कौन करेगा?, कौन लाएगा?, कौन जाकर बोर्ड साफ़ करेगा? हमेशा पुल्लिंग में होती हैं। कक्षा में बैठी लड़कियाँ अनजाने ही इन वाक्यों से बाहर रह जाती हैं। यदि शिक्षक कहते कौन करेगा या करेगी? तो भाषा में ही बराबरी की खिड़की खुल जाती।

कुछ विद्यालयों में तो समूहों के नाम तक इस असमानता से प्रभावित होते हैं। कई स्कूलों में केवल पुरुष महापुरुषों गांधी, नेहरू, विवेकानंद, भगतसिंह के नाम पर समूह बनाए जाते हैं। प्रेरणादायक महिलाओं जैसे रानी लक्ष्मीबाई, रानी कमलापति, अवंतिबाई, कल्पना चावला, टेस्सी थॉमस, सुधा मूर्ति या अन्य महिला वैज्ञानिकों, खिलाड़ियों, लेखिकाओं के नाम शायद ही किसी को सूझते हैं। जब बच्चों के सामने आदर्शों के रूप में केवल पुरुष चेहरे आते हैं, तो संदेश यह जाता है कि नेतृत्व और पराक्रम का चेहरा भी मात्र पुरुष ही है।

भाषा की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह संवाद का माध्यम होते हुए भी अनजाने ही जेंडर असमानता को ढोती रहती है। 'करेगा', 'लाएगा', 'नेता बना', 'मर्द बनो' जैसे वाक्य हमारे अवचेतन में पुरुष-प्रधान सोच को पुख्ता करते हैं। भाषा ऐसे विचारों को वैधता देती है जिन्हें हम शायद सचेत रूप से नहीं मानते।

पाठ्यपुस्तकों में भी इसी असमानता की झलक है। ज्यादातर उदाहरणों में 'रवि', 'सुमित', 'राजेश' विज्ञान प्रयोग करते, खेल जीतते या पुरस्कार पाते दिखते हैं। जबकि लड़कियों के हिस्से में 'रीना माँ की मदद करती है' या 'सीमा गुड़िया से खेलती है' जैसे दृश्य आते हैं। इससे बच्चों के मन में यह धारणा मजबूत होती है कि सक्रियता और खोज लड़कों का क्षेत्र है, जबकि देखभाल और सहयोग लड़कियों का।

घर और समाज की रोज़मर्रा की भाषा भी इस सोच को बढ़ाती है लड़की होकर ऐसे बोलती है?, बेटी, घर का ध्यान रखो, बेटे, बाहर का काम तुम संभालो। यहाँ शब्दों के जरिए भूमिकाएँ बाँट दी जाती हैं एक भीतर की, एक बाहर की। पड़ोस में भी सुनने को मिलता है हमारे घर का बेटा इंजीनियर बनेगा, जबकि बेटी के लिए कहा जाता है अच्छे घर में शादी होगी। आकांक्षाओं में यह फर्क भाषा ही पैदा करती है।

जर्नल ऑफ लैंग्वेज एंड सोशल साइकोलॉजी (2018) के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों को उनकी पहचान के अनुरूप सकारात्मक संबोधन मिलते हैं, उनमें आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता अधिक विकसित होती है। यानी शब्द बच्चों के भविष्य का आधार गढ़ते हैं। भाषा में छिपी असमानता अवसरों पर भी असर डालती है।

यूनिसेफ़ और यूनेस्को (2023) की रिपोर्ट बताती है कि प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन 95 फीसदी से अधिक है, पर उच्च माध्यमिक स्तर तक यह घटकर 68 फीसदी रह जाता है। यह कमी केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि सामाजिक अपेक्षाओं और भाषा में निहित सोच से भी आती है।

NFHS-5 (2019-21) के अनुसार ग्रामीण इलाकों में 15-19 वर्ष की 16 फीसदी लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पातीं; शहरी क्षेत्रों में यह 8 फीसदी है। मध्यप्रदेश में स्थिति और स्पष्ट दिखाई देती है उच्च माध्यमिक स्तर पर लड़कियों की उपस्थिति लड़कों से लगभग 10 फीसदी कम है। वहीं 2025-26 में RTE ऑनलाइन लॉटरी के तहत 83,483 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश मिला, जिनमें 40,120 लड़कियाँ थीं, सुधार तो दिखता है, पर समानता अभी भी दूर है। प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों का नामांकन 92 फीसदी है, पर माध्यमिक स्तर पर यह घटकर 70 फीसदी रह जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 12-14 वर्ष की लगभग 11 फीसदी लड़कियाँ स्कूल छोड़ देती हैं। यह बताता है कि अवसर बढ़े हैं, लेकिन सोच अभी भी बराबरी तक नहीं पहुँची है।

अब सवाल यह है कि इस असमानता को दूर कैसे किया जाए? पहला कदम दैनदिंनी भाषा से शुरुआत करने का है। स्कूलों और शिक्षकों को समझना होगा कि 'बेटा' या 'छात्र' जैसे शब्द केवल लड़कों तक सीमित नहीं होने चाहिए। इनकी जगह 'बच्चों', 'विद्यार्थियों' या 'प्रिय विद्यार्थिनी और विद्यार्थी' जैसे संबोधन अपनाए जा सकते हैं।

शिक्षकों को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण होने चाहिए ताकि वे समझ बना सकें कि उनके प्रस्तुत किये जाने वाले शब्द बच्चों की आत्म-छवि पर कितना असर डालते हैं। पाठ्यपुस्तकों में भी लड़कियों को डॉक्टर, वैज्ञानिक, नेता और खिलाड़ी के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। स्कूलों को खेल, विज्ञान, वाद-विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों में लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। अभिभावकों को भी संवाद सत्रों के माध्यम से यह समझाया जाना चाहिए कि भाषा और व्यवहार में समानता अपनाना क्यों जरूरी है।

बदलाव कठिन नहीं है, यह केवल सोच और आदत का प्रश्न है। भाषा में जेंडर असमानता को हटाना शायद तुरंत समाज की तस्वीर न बदले, पर यह बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। यह बदलाव बच्चों को यह एहसास कराएगा कि वे जो हैं, उसी रूप में मूल्यवान हैं चाहे बेटा हों या बेटी।

अंतत: यह स्वीकार करना होगा कि भाषा हमारी सोच को आकार देती है। शब्द केवल मुख से नहीं निकलते, वे हमारे भीतर बसते हैं और आने वाली पीढ़ियों की मानसिकता का आधार बन जाते हैं। यदि हम सचमुच समानता का समाज चाहते हैं, तो भाषा को भी समानता का दर्पण बनाना होगा। यही शिक्षा का सच्चा उद्देश्य है और यही समाज का भविष्य भी।

विश्व बाल दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।

मेरा दिन, मेरे अधिकार-हर बच्चे की आवाज को सुने दुनिया

बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करने, बच्चों की समस्याओं को हल करने, बच्चों के बीच जागरूकता तथा बच्चों के कल्याण के लिए काम करने और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनियाभर में 20 नवम्बर को 'विश्व बाल दिवस' मनाया जाता है। यह दिवस बच्चों के अधिकारों की वकालत करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करता है। व्यस्कों से अलग बच्चों के अधिकारों को 'बाल अधिकार' कहा जाता है। सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल दिवस की शुरूआत किए जाने का मूल उद्देश्य बच्चों की जरूरतों को पहचानना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण को रोकना है ताकि बच्चों का समुचित विकास हो सके। विश्व बाल दिवस प्रतिवर्ष एक खास विषय के साथ मनाया जाता है, जो इस वर्ष 'मेरा दिन, मेरे अधिकार' विषय के साथ मनाया जा रहा है। यह विषय दुनिया को याद दिलाता है कि हर बच्चे को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और शोषण-मुक्त जीवन का अधिकार है। आज जब बाल तस्करी, कुपोषण, युद्ध, भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य जैसी चुनौतियां बच्चों को प्रभावित कर रही हैं, तब यह दिवस हमें उनके भविष्य के प्रति और अधिक संवेदनशील बनने का आह्वान करता है। बाल अधिकारों की रक्षा ही एक सुरक्षित और समृद्ध विश्व की बुनियाद है।

हालांकि भारतीय संविधान में बच्चों के कई अधिकार निर्धारित हैं। हमारे संविधान के अनुसार प्रत्येक बच्चे को जिंदा रहने का मौलिक अधिकार है और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य पर है। हर राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को किसी भी तरह के भेदभाव से बचाए और उनके अधिकारों को बढ़ाने के लिए उचित कदम उठाए। बच्चे को उच्चतम स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा पाने का अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चे के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य करे। प्रत्येक बच्चे को अच्छा जीवन स्तर पाने का अधिकार है। अक्षम बच्चे को विशेष देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण पाने का अधिकार है। बच्चे को नशीली दवाओं, मादक पदार्थों के उपयोग से बचाए जाने का अधिकार है। राज्य का यह कर्तव्य है वह बच्चों को हर तरह के दुर्व्यवहार से बचाए। समाज के अनाथ बच्चों को सुरक्षा पाने का अधिकार है, बच्चों को ऐसे कार्यों से बचाए जाने का अधिकार है, जो उसके स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास को हानि पहुंचाएं। किसी बच्चे को बेचना, अपहरण करना या जबरन काम करवाना कानूनी अपराध है, राज्य की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह बच्चे को इससे बचाए। राज्य की यह भी जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को यौन अत्याचारों, वेश्यावृत्ति आदि से बचाए।

विश्व बाल दिवस मनाने की शुरुआत वैसे तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी लेकिन वास्तव में यह दिवस वर्ष 1857 में जून के दूसरे रविवार को चेल्सी (मैसाचुसेट्स) में यूनिवर्सल ऑफ द रिडीमर के पादरी रेवरेंड डा. चार्ल्स लियोनार्ड ने शुरू किया था। लियोनार्ड ने बच्चों के लिए और उनके लिए समर्पित एक विशेष सेवा का आयोजन किया था, जिसे 'रोज डे' का नाम दिया था, कुछ समय बाद इसे 'फ्लावर संडे' नाम दिया गया और बाद में इसका नाम 'चिल्ड्रन्स डे' कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर बाल दिवस पर पहली बार 1920 में तुर्की गणराज्य द्वारा 23 अप्रैल की निर्धारित तिथि के साथ राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। 1920 से तुर्की सरकार और उस समय के समाचारपत्रों ने बाल दिवस को बच्चों के लिए एक दिन घोषित करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मनाया। हालांकि इसकी अधिकारिक घोषणा 1929 में तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति मुस्तफा केमल अतातुर्क द्वारा की गई थी। बाल दिवस मनाए जाने की शुरूआत वैसे तो 1920 के दशक में ही हो गई थी लेकिन वैश्विक रूप में देखें तो दुनियाभर में इसे मान्यता 1953 में मिली। विश्वभर में बाल दिवस मनाए जाने का विचार भारत के पूर्व रक्षामंत्री वी के कृष्ण मेनन का था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्वभर के तमाम देशों से अपील की गई थी कि वे अपनी परम्पराओं, संस्कृति तथा धर्म के अनुसार अपने लिए कोई एक ऐसा दिन सुनिश्चित करें, जो सिर्फ बच्चों को ही समर्पित हो। हालांकि बाल दिवस सर्वप्रथम जेनेवा की 'इंटरनेशनल यूनियन फॉर चाइल्ड वेलफेयर' के सहयोग से अक्टूबर 1953 में विश्वभर में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की स्थापना 1954 में की गई थी किन्तु 1959 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा के विस्तारित रूप को अपनाया।

20 नवम्बर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि 20 नवम्बर 1959 को संयुक्त राष्ट्र की आमसभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार, बाल अधिकारों को इन चार अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है।

20 नवम्बर 1989 को बच्चों के अधिकारों के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे 191 देशों द्वारा पारित किया गया। बाल दिवस मनाए जाने को लेकर दिलचस्प तथ्य यह है कि भले ही विश्व बाल दिवस 20 नवम्बर को मनाया जाता है लेकिन विश्व के अनेक देशों में इसे मनाने की तारीखें अलग-अलग हैं। जनवरी माह से लेकर दिसम्बर तक हर माह किसी न किसी देश में बाल दिवस का आयोजन होता है। माना जाता है कि सबसे पहले बाल दिवस तुर्की में मनाया गया था। दुनियाभर में 191 देशों द्वारा बाल दिवस मनाया जाता है, जिनमें से करीब चार दर्जन देश 20 नवम्बर को यह दिवस मनाते हैं जबकि अन्य देश अपने हिसाब से अन्य तिथियों पर। भले ही अपनी-अपनी सहूलियत के आधार पर विभिन्न देशों द्वारा अलग-अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है लेकिन हर जगह बाल दिवस मनाए जाने का मूल उद्देश्य यही है कि इसके जरिये लोगों को बच्चों के अधिकारों तथा सुरक्षा के लिए जागरूक किया जा सके। दुनियाभर में बाल दिवस के माध्यम से लोगों को बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल मजदूरी इत्यादि बच्चों के अधिकारों के प्रति जगरूक करने का प्रयास किया जाता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा बच्चे भीख मांगते हैं और यौन शोषण के शिकार होते हैं। विश्व बाल दिवस सही मायनों में विश्वभर में बच्चों के अधिकारों के प्रति एकजुटता को बढ़ावा देने का समय है। दुनिया के हर कोने में बच्चों की समस्याओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी, तभी बच्चों की विभिन समस्याओं का निदान होने की उम्मीद की जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा का उद्देश्य यही था कि इस विशेष दिन के माध्यम से अलग-अलग देशों के बच्चे एक-दूसरे के साथ जुड़ सकें, जिससे उनके बीच आपसी समझ तथा एकता की भावना मजबूत हो। किसी भी राष्ट्र का विकास सीधे तौर पर वहां के बच्चों के विकास से जुड़ा होता है। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं और यदि वे ही अपने बाल अधिकारों से वंचित रह जाएंगे तो एक बेहतर दुनिया के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस विशेष अवसर पर न सिर्फ बच्चों से जुड़ी तमाम समस्याओं के समाधान का संकल्प लिया जाए बल्कि उसे क्रियान्वित करने के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएं।

याद पुरानी

विष्णु बैरागी

लेखक स्तंभकार हैं।

'वह' धूमधड़ाके से आती थी

पुराने कागज-पत्तर टटोलते-टटोलते, भोपाल से प्रकाशित 'पीपुल्स समचार' का, 07 मार्च 2009 का पन्ना हाथ में आ गया। कौतूहल से देखा तो कस्बाई फिल्म के आगमन की मेरी एक 'याद' इसमें छपी नजर आई।)

ईशान छठवीं कक्षा में पढ़ रहा है। चुप बिल्कुल ही नहीं बैठ पाता। 'बाल बिच्छू' की तरह सक्रिय बना रहता है। उसे पूरे शहर की खबर रहती है। मैं उसके ठीक पड़ौस में रहता हूँ-एक दीवाल की दूरी पर। आज सवेरे उससे कहा - 'स्लमडाग करोड़पति' लगे तो मुझे कहना। देखने चलेंगे।' सुनकर उसने मुझे आश्चर्य और मेरे प्रति दया भाव से देखा। बोला - 'अरे! दादाजी, वह तो आकर चली भी गई!'

मुझे धक्का लगा। इसलिए नहीं कि मैं वह फिल्म नहीं देख पाया। इसलिए कि जिस फिल्म का डंका पूरे देश-दुनिया में बज रहा है, जिसकी 'जय हो' से गली-गली गुंजायमान है, जिसे 'ऑस्कर' मिलने की कल्पना मात्र से देश का आभिजात्य वर्ग ही नहीं, 'ऑस्कर' का अर्थ न समझने वाला मध्य वर्ग भी पुलकित हो रहा है, वह फिल्म मेरे कस्बे में कब आई और कब चली गई, पता ही नहीं लगा! हाथी गली में होकर निकल गया और पत्ता भी नहीं खड़का? वह भी तब, जबकि सिनेमा घर मेरे निवास से तीन सौ मीटर दूर भी नहीं?

मुझे मेरे स्कूली दिनों वाला मेरा पैतृक गाँव मनासा और वहाँ का 'जगदीश टॉकीज' याद आ गया। 'नगर सेठ भैया साहब झँवर' उसे चलाते थे। तब जनसंख्या यही कोई नौ-दस हजार रही होगी मेरे मनासा की। 'श्री बद्री विशाल मन्दिर' के बाद गाँव का सबसे बड़ा आकर्षण यह 'जगदीश टॉकीज' ही था। अल्हेड़ दरवाजे और बस स्टैण्ड के बीचों-बीच। आस-पड़ोस के गाँवों के प्रवासी यात्री, अपना सामान अपने साथ वाले के जिम्मे कर, भरी-दोपहर में यह टॉकीज देखने आते। सन्नाटा होता था उस समय टाकीज के प्रांगण में। और तो और, उसमें लगी होटल भी सुनसान रहती। फिर भी लोग आते, टाकीज के बरामदे में लगे, 'चालू फिल्म' के पोस्टर और 'स्टिल्स' देखते और अपने गाँव जाकर, 'अनूठी उपलब्धि' की तरह इस 'टाकीज-दर्शन' का बखान किसी परी कथा की तरह करते।

फिल्म का बदलना तब पूरे गाँव की बड़ी घटना होता था। तीन-चार दिन पहले ही पता हो जाता था कि फलाँ फिल्म लगने वाली है। 'नई' फिल्म के पोस्टर चिपके बोर्ड, गाँव की गली-गली में घुमाए जाते। लकड़ी की फ्रेम पर, जूते गाँठने वाली वाली कीलों से ठुके टाट पर चूना पोतकर इबारत की जमीन बनाई जाती और उस पर नीले, लाल, काले रंगों से फिल्म के नाम तथा अन्य ब्यौरे लिखे जाते। बोर्ड का आकार सामान्यत: 4 गुणा 4 फुट होता। उन दिनों कोई भी फिल्म रीलीज होने के बरसों बाद ही मेरे गाँव जैसे 'सेण्टर' तक आ पाती थी। (तब किसी फिल्म की रीलीज के समय 10 प्रिण्ट जारी करना 'धमाका खबर' होता था) । सो, तब तक फिल्म की 'सफलता और हैसियत' सबको मालूम हो चुकी होती थी। बोर्डों की और इबारत के रंगों की संख्या का निर्धारण, फिल्म की इसी सफलता और हैसियत के अनुसार होता। इन बोर्डों की संख्या सामान्यत: दो ही होती। प्रत्येक बोर्ड को दो बच्चे उठाए होते। मुफ्त में फिल्म देखना इन बच्चों का पारिश्रमिक होता।

फिल्म की हैसियत के अनुसार ही बोर्डों को गलियों में घुमाया जाता। सामान्यत: दो-दो बोर्ड घुमा दिए जाते। कोई ठीक-ठीक फिल्म होती तो बोर्डों के आगे 'मोहम्मद हुसैन बा' साहब के बैण्ड' का एक ट्रम्पेटवादक और एक ड्रमर चल रहा होता। 'हिन्दुस्तान के शहरों में कामयाबी के झण्डे गाड़ने वाली' फिल्म होती तो बोर्डों की संख्या ही नहीं, बोर्डों का आकार भी बढ़ जाता और बैण्ड के सदस्यों की संख्या भी। लाउडस्पीकर का चलन उन दिनों नहीं था। बोर्डों के ठीक पीछे एक उद्घोषक चल रहा होता, जिसके पास टीन का बना भोंपू होता। वह अपनी पूरी ताकत से फिल्म की खूबियाँ बखान करता। जैसे कि 'हिमालय के सच्चे सीनों से भरपूर, महान, धार्मिक फिल्म.....' या 'मार-धाड़ से भरपूर, किंगकांग और दारासिंह की दिल हिला देने वाली कुश्तियाँ.....' या 'नाच-गाने से

भरपूर, माँ-बहनों के साथ देखने वाली शानदार सामाजिक फिल्म.....' आदि-आदि। उन दिनों फिल्में 'श्वेत-श्याम' ही हुआ करती थीं और रंगीन की शुरुआत हुई ही थी। कुछ गीतों का फिल्मांकन रंगीन हुआ करता था। ऐसे रंगीन गीत फिल्म का विशेष आकर्षण होते और उद्घोषक को याद रख कर अलग से कहना पड़ता - 'तीन रंगीन पार्ट सहित।'

जिस दिन फिल्म बदलती उस दिन पहला शो, अपने निर्धारित समय शाम 6 बजे से कोई आधा घण्टा देर से शुरू होता। फिल्म का प्रिंट इन्दौर से आता। इन्दौर से चलकर रामपुरा जाने वाली बस शाम कोई 6 बजे मेरे गाँव पहुँचती। बस के आने से काफी पहले ही लोग बस स्टैण्ड पहुँच जाते। टाकीज का कर्मचारी सबसे बाद में पहुँचता। वह किसी नायक की तरह प्रकट होता और ऐसे व्यवहार करता मानो कोई चमत्कार करने वाला हो। फिल्म का प्रिण्ट, टीन के बक्से (पेटी) में गोल डिब्बों में बन्द होता। जितने गोल डिब्बे होते, फिल्म उतनी ही रीलों वाली होती।

फिल्म प्रिंट के आने को 'फिल्म की पेटी' आना कहा-जाता। बस आती। दूर से, बस की छत पर रखी 'फिल्म की पेटी' देखने की कोशिश शुरू हो जाती। बस आकर, स्टैण्ड पर व्यवस्थित खड़ी होने के लिए रिवर्स होती। बस का खलासी, चलती बस का पिछली फाटक खोल कर तेजी से उतरता और बस के पिछवाड़े, ड्रायवर साइड जाकर 'आने दो! टाने दो!!' की आवाज लगा कर बस को खड़ी करवाता।

बस रुकते ही खलासी छत पर चढ़ता। बाकी सवारियों के सामान को अनदेखी कर, सबसे पहले 'फिल्म की पेटी' झेलता। पेटी ठेले पर रखी जाती। टाकीज के कर्मचारी से पहले, वहाँ जुटे लोग उचक-उचक कर, पेटी पर चिपका लेबल देखते। जो सबसे पहले देख लेता, जोर से चिल्लाता - '16 रील की है।' पेटी को जुलूस की शकल में टाकीज तक लाया जाता। उसके बाद शो की तैयारी शुरू होती।

मेरे गाँव के टॉकीज में आने वाली प्रत्येक 'नई' फिल्म इसी तरह आती। यह क्रम मेरे गाव की जिन्दगी का स्थायी हिस्सा बना रहा। कोई भी फिल्म, कभी भी चुपचाप नहीं आई। जो भी आई, अपनी हैसियत के मुताबिक धूम-धड़ाके से आई। और केवल आने पर ही चर्चित नहीं रही। जाने के बाद भी उसकी चर्चा होती रहती।

आज दुनिया एक गाँव में बदल गई है। अंगुलियों की पोरों की एक हरकत सारी दुनिया की नवीनतम जानकारी, कम्प्यूटर के पर्दे के जरिए घर-घर में, एक पल में पहुँच रही है। अखबार, छपने से पहले ही बासी होने लगे हैं। ऐसे जीवन्त समय में, 'स्लगडॉग करोड़पति' मेरे कस्बे में, मेरे घर से तीन सौ मीटर दूर स्थित सिनेमा घर में लग कर उतर गई और मुझे भनक तक नहीं पड़ी! यकीनन यह मेरी असावधानी तो है ही, किन्तु फिल्मों के प्रति हमारे सार्वजनिक व्यवहार का परिचायक भी है।

अमलतास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उच्च-जोखिम नवजात शिशु क्लिनिक का शुभारम्भ

देवास। अमलतास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, देवास ने नवजात शिशुओं की विशेष देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुधवार को अमलतास अस्पताल में उच्च-जोखिम नवजात शिशु क्लिनिक का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्री आनंद मालवीय, एस.डी.एम. देवास, के करकमलों द्वारा किया गया। शिशु रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. नेहा काकानी ने मुख्य अतिथि का स्वागत कर बताया की उच्च-जोखिम नवजात शिशु क्लिनिक एक विशेष चिकित्सा सुविधा है जो उन नवजात शिशुओं की देखभाल और अनुवर्ती देखभाल के लिए समर्पित है जिन्हें जन्म के समय गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन शिशुओं में अक्सर समय से पहले जन्मे बच्चे, कम वजन वाले, जन्मजात विकृतियाँ, संक्रमण या मातृ स्थितियों से उत्पन्न जटिलताएँ शामिल होती हैं। क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य निरंतर चिकित्सा सहायता प्रदान करना, शारीरिक विकास में वृद्धि करना और दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने वाले उपाय प्रदान करना है। शुभारम्भ समारोह में विशेषज्ञों द्वारा भारत में नवजात शिशु की देखभाल की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर बताया की हाल ही के राष्ट्रीय आँकड़ों के अनुसार, भारत में प्रति 1000 जन्म पर 19 नवजातों की मृत्यु होती है, जबकि मध्यप्रदेश में यह दर 29 है।

अस्पताल प्रबंधन ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए, चेयरमैन महोदय के मार्गदर्शन में एनआईसी और एचडीयू सुविधाओं को मजबूत करने के साथ ही इस उच्च-जोखिम क्लिनिक की शुरुआत की है। क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य हर हाई रिस्क बेबी को सुरक्षित, सक्षम और संवेदनशील देखभाल देना है ताकि नवजात मृत्यु दर को कम किया जा सके। यह शुभारम्भ समारोह न्यूबॉर्न केयर वीक के अवसर पर आयोजित किया गया, जो हमें याद दिलाता है कि हर नवजात शिशु की शुरुआत सुरक्षित होनी चाहिए। उद्घाटन के दौरान, मुख्य अतिथि द्वारा स्वस्थ नवजात शिशुओ के माताओं को बेबी किट भी प्रदान की गई। इस क्लिनिक में मुफ्त टीकाकरण की सुविधा डीआईओ डॉ. सुनील तिवारी द्वारा प्रत्येक बुधवार को प्रदान की जाएगी।इस अवसर पर अमलतास विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉ. शरदचन्द्र वानखेड़े, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. ए.के. पिठवा, अस्पताल निदेशक डॉ. प्रशांत, विभागाध्यक्ष डॉ. अभय गुप्ता, और शिशु रोग विभाग के विशेषज्ञ डॉ. शाहबाज खान, डॉ. आशुतोष शर्मा, डॉ. शर्मिला मित्तल, डॉ. पूजा, डॉ. शिल्पा जैन, रेटिना विशेषज्ञ डॉ. पूर्वी गार्गे, फिजियोथेरेपी हेड डॉ.नेहा , जूनियर रेसिडेंट, इन्टर्न, विद्यार्थियों सहित समस्त विभागीय प्रमुख और स्टाफ उपस्थित थे। अमलतास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चेयरमैन श्री मयंक राज सिंह भदौरिया जी द्वारा बताया गया की अमलतास अस्पताल में, हमने न केवल एनआईसी और एचडी जैसी विश्व-स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं, बल्कि अब इस उच्च-जोखिम नवजात शिशु क्लिनिक की शुरुआत कर रहे हैं। जिसका उद्देश्य स्पष्ट है- हर नवजात महत्वपूर्ण है। इस क्लिनिक के माध्यम से, हमारा लक्ष्य है कि हम हर हाई-रिस्क बच्चे को सुरक्षित, सक्षम, और संवेदनशील देखभाल प्रदान करें, ताकि उन्हें स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया जा सके और हम मिलकर नवजात मृत्यु दर को कम करने में सफल हों।

प्रमुख सचिव श्री यादव की अध्यक्षता में हुई राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक

भोपाल । प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा श्री संदीप यादव की अध्यक्षता में गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड पी.सी.पी.एन.डी.टी. की बैठक में अनेक निर्णय लिये गये। बैठक में विधानसभा सदस्य श्रीमती प्रियंका मीणा, आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री तरुण राठी, अतिरिक्त सचिव विधि एवं विधायी कार्य श्री निशित खरे सहित विभिन्न विभागीय अधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभागिता की गयी।

राज्य सुपरवाइजरी बोर्ड की बैठक में लिये गये मुख्य निर्णयों में मध्यप्रदेश में भ्रूण लिंग चयन संबंधी सूचना तंत्र को सुदृढ़ करने एवं सामाजिक भागीदारिता को बढ़ावा देने के लिये पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना संचालित है, जिसका प्रदेश में अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाये। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पुनरीक्षित मुखबिर पुरस्कार योजना अंतर्गत 2 लाख रुपये के पुरस्कार का प्रावधान है, जिसमें मुखबिर के सूचना पर पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम अंतर्गत प्रकरण सफल स्टिंग ऑपरेशन होने अथवा प्रकरण पंजीबद्ध होने पर मुखबिर या सूचनादाता को 50 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। साथ ही न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण में दंडित किये जाने पर मुखबिर या सूचनादाता को पुनः 30 हजार रुपये दिये जाने का प्रावधान है। पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा-22 अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, संगठन, केन्द्र द्वारा लिंग चयन सुविधाओं के संबंध में किसी भी प्रकार का विज्ञापन भौतिक या इंटरनेट के माध्यम से प्रकाशन, वितरण एवं संसूचित करने पर प्रतिबंध है।

लिंग चयन के संबंध में साइबर एडवर्टाइजमेंट, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर बेची जा रही सामग्री, इंटरनेट पर उपलब्ध आपत्तिजनक ब्लॉग्स/वीडियोज आदि को साइबर निगरानी द्वारा नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है। इसके लिये विभाग द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, इंटेलिजेंस के समन्वय से सुदृढ़ कार्यवाही पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 एवं आई.टी. अधिनियम, 2000 के स्थापित प्रावधान अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। समाज में लिंग चयन आधारित गर्भपात से संभावित सामाजिक असंतुलन एवं लैंगिक हिंसा के नियंत्रण के लिये जन-प्रतिनिधियों के सोशल मीडिया पेज तथा जिलों के आधिकारिक वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से सामाजिक जागरूकता एवं जन-भागीदारी सुनिश्चित की जायेगी।

इंदिरा जी की जयंती पर

'सम्यक अभियान इंदिरा ज्योति एवं चलें रामराज्य की ओर' अभियान का शुभारम्भ

भोपाल। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, लौह इच्छाशक्ति की प्रतीक और देश की आत्मा में रची-बसी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के 108वें जन्मदिवस के अवसर पर आज भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर 'सम्यक अभियान इंदिरा ज्योति एवं चलें रामराज्य की ओर' अभियान का शुभारम्भ किया गया। और कार्यक्रम के अंत हरि झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारम्भ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा जी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया ।

इस आयोजन में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कांतिलाल भूरिया, श्री अरुण यादव,विधायक श्री आरिफ मसूद, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया,पूर्व सांसद श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री राजमणि पटेल, पूर्व मंत्री श्री मुकेश नायक, वरिष्ठ नेता श्री राजेन्द्र मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक श्री भास्कर रोकड़े, सम्यक अभियान के प्रभारी श्री शैलेन्द्र श्रीवास्तव, श्री संजय कामले, श्री प्रवीण सक्सेना, श्री योगेश यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसजन उपस्थित रहे। इसके साथ ही प्रदेश प्रवक्ता श्री भूपेन्द्र गुप्ता, श्री रवि सक्सेना, श्री अवनीश बुंदेला, श्री आनंद जाट, श्री प्रवीण धौलपुरिया, श्री विक्रम चौधरी, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप परमार और प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल राज भी कार्यक्रम में शामिल रहे।

चलें रामराज्य की ओर अभियान के लिए गठित कोर कमेटी में समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व और जिम्मेदारी दी गई है। यह अभियान न्यायपूर्ण, समतामूलक, करुणामय और संवेदनशील शासन-व्यवस्था की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास है, जिसमें किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, कमजोर और वंचित वर्गों की भागीदारी और आवाज़ को प्राथमिकता दी जा रही है।

सम्यक अभियान के तहत इंदिरा ज्योति कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री पवन खेड़ा जी ने चलें रामराज्य की ओर अभियान का शुभारम्भ किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे वैचारिक और जनजागरण से जुड़े कार्यक्रम केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी आयोजित होने चाहिए।

पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त अन्तरित की

● धार जिले को मिला बड़ा लाभ

धार । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की गई। धार जिले के दो लाख से अधिक किसानों को इस पहल का प्रत्यक्ष लाभ मिला। 46 करोड़ से अधिक की राशि धार जिले के 2,31,024 किसानों के बैंक खातों में सीधे अंतरित की गई, जिससे किसानों को आर्थिक संबल प्राप्त हुआ।केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और सीईओ जिला पंचायत अभिषेक चौधरी ने धार कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर सहभागिता की। इस अवसर पर महंत निलेश भारती,जनप्रतिनिधिगण,अधिकारी,कर्मचारी और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने संबोधन के दौरान कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और सबसे अधिक परिश्रम करते हैं। उन्होंने बताया कि धार ज़िले में रेलवे लाइन की सुविधा किसानों की प्रमुख आवश्यकता है और इसे प्राथमिकता से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की वास्तविक चिंता करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप खाद, बिजली और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है। उन्होंने उल्लेख किया कि किसान सम्मान निधि के तहत 46 करोड़ से अधिक की राशि का वितरण किसानों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आरक्षण के निर्णय को भी उन्होंने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को ब्याजमुक्त ऋण, 24 घंटे बिजली और पर्याप्त अन्न भंडार जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। यह सब किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार के निरंतर सहयोग से संभव हुआ है।

जलसंकट के समय नगरपालिका को आती है कुओं की याद

शहर के कुएं खाली, सालों से नहीं हुई सफाई

बैतूल। कुएं का जल संरक्षण के लिए काफी महत्व है, लेकिन शहर के कुएं जागरूकता व देखरेख के अभाव में सूखे हुए है। इन कुंओं की याद नगरपालिका को उस समय ही आती है, जब शहर में भीषण जलसंकट का समय आता है, जबकि इन कुंओं ने 13 साल पहले 2012 में पूरे शहर को जलसंकट से उबारा था, वे आज भी शहर के लिए पानी स्टोरेज करने को तैयार हैं, लेकिन इनमें पानी जाने के रास्ते ही बंद हैं। नगरपालिका के ध्यान नहीं देने के कारण इतनी, बारिश होने के बावजूद ये कुएं लबालब नहीं हुए। इनमें कचरा तैर रहा है, जिसे साफ करवाने की जरूरत है। बता दे कि 2017 की गर्मियों में जलसंकट के दौरान नगरपालिका ने शहर के 42 कुओं की सफाई करवाई थी, इन्हें पेंट कर इन पर पानी बचाने और पर्यावरण संतुलन के स्लोगन भी लिखे थे। लेकिन अब अधिकांश कुओं में पानी जाने के रास्ते बंद हैं। यदि इनमें पानी जाने के लिए नालियां ही बना दी जाएं तो ये भरा जाएंगे, इससे भूजलस्तर तो बढ़ेगा ही साथ ही जलसंकट गहराने पर इनका पानी जन उपयोग में लिया जा सकेगा।

नपा की अनदेखी और जागरूकता के अभाव- शहर के कुछ कुओं में जलस्तर अच्छा है लेकिन जागरूकता के अभाव में गंदगी कुएं में बढ़ रही है जिससे कुएं का पानी का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोग कुएं में ही गंदगी फेंक देते हैं। नगरपालिका द्वारा सार्वजनिक कुओं की सफाई नहीं कराई जाती है। जबकि कुछ साल पहले तक शहरवासियों के पानी का मुख्य स्त्रोत कुंए ही रहा करते थे और लोग पीने के अलावा निस्तारी के लिए भी जल का उपयोग करते थे। लेकिन अब यह कुएं देखरेख और जागरूकता के शिकार हो गये है। इसके पीछे कारण यह है

कि अब लोग आधुनिक हो गये है। घरों में कुओं की अपेक्षा बोर करवा लिया है। जिससे आसानीपूर्वक पानी मिल जाता है और मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती है।

शहर के इन क्षेत्रों में सूखे है कुंए - जानकार बताते है कि कई साल हले शहर में आधा सैकड़ा से अधिक कुएं हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ लोग आधुनिक हो गये। लोगों के घरों में सहूलियत बढ़ती गई और लोगों ने अपने घरों में बोर और हैंडपंप लगवाना शुरू कर दिया। जिसके कारण धीरे-धीरे कुंओं का अस्तित्व कम होने लगा। अभी भी शहर के पुलिस लाइन्स, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, सदर नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के पीछे, सिविल लाइन्स तासी क्लब के समीप के कुएं, मोती वार्ड के अधिकांश कुएं है, जो नगरपालिका की अनदेखी के कारण सूखे हैं। इन कुंओं को पुनर्जीवित किया जाये तो यह आधे से अधिक शहर को पानी दे सकते है, लेकिन इन कुओं को पुनर्जीवित करने न तो नपा और न ही प्रशासन का ध्यान दे रहा है।

4 करोड़ लीटर पानी हो सकता है स्टोर - शहर के कुओं की सफाई कर उसमें पानी जाने के लिए रास्ते बनाये जाये तो यह कुंए आधे से अधिक शहर की प्यास बुझा सकते है। जानकार बताते है कि प्रत्येक कुएं में 10 लाख लीटर पानी स्टोर हो सकता है। इस अनुमान से 42 कुओं में 4 करोड़ 20 लाख लीटर पानी स्टोर हो सकता था। बताया गया कि सीमा से सटे गांवों में ही जल संरक्षण के प्रति दिखाई जागरूकता के कारण यहां कुएं लबालब हैं। चिखलार गांव में गर्मियों में ही कुओं के आसपास सोकपिट बनाकर पत्थर डाले गए थे। इन सोकपिट से पाइप बिछाकर कुएं तक डाले गए थे। अब ये कुएं ऊपर तक भर गए हैं।

इनका कहना है - शहर के जो भी कुएं हैं, उनके आसपास सफाई करवाकर पानी जाने के रास्ते बनवाए जाएंगे। जिन कुओं की दोबारा सफाई की जरूरत होगी, उन्हें साफ करवाया जाएगा।

सतीश मटसेनिया, सीएमओ, नगरपालिका बैतूल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खण्डेलवाल की सेवाभाव पहल

दिव्यांग युवक को मिली मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल की सौगात

बैतूल। क्षेत्र के चहुंमुखी विकास, आमजन की समस्याओं का संतुस्टिकारक निराकरण और संगठन को मजबूत करनें के साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल सेवाभावी कार्यो में सतत जुटे हुए है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जरूरतमंद और दिव्यांगों को मदद कर उन्हे सशक्त बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल रहता है। गत दिनों बैतूल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैतूल बाजार मंडल के भ्रमण के दौरान ग्राम सेलगॉव मे दिव्यांग अलकेश साहू ने जब उन्हे दिव्यांगता का हवाला देकर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल दिलवाने की गुहार लगाई तो व्यस्त दौरे के बावजूद श्री खण्डेलवाल ने मोबाइल पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण विभाग बैतूल की उपसंचालक से सम्पर्क कर अलकेश साहू को मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल की संवेदनशील पहल पर अलकेश साहू को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल की सौगात मिल गई। बीते लगभग तीन वर्षो से बिस्तर पर रहने वाला अलेकश अब गांव भर में घूमने लगा है। जिससे उसके चेहरे पर लौटी मुस्कान ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया है। साथ ही उसका जीवन भी आसान हो गया।

तीन वर्षो से बिस्तर पर था अलकेश - सेलगांव निवासी अलकेश साहू (34) वर्ष ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व हुए एक्सीडेंट में गंभीर चोट आनें से उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। फिर भी वह हिम्मत करके अपने दैनिक कार्य करने के साथ ही लकड़ी के सहारे चल फिर लेता था। अलकेश के मुताबिक बीते लगभग तीन वर्ष पूर्व उसके कमर के नीचे का हिस्सा अचानक निष्क्रिय हो गया था। उपचार के बाद भी स्थिति मे कोई सुधार नहीं आया। परिणाम स्वरूप बीते तीन वर्षो से वह बिस्तर पर ही रहता था। परिवार की मदद से वह दैनिक कार्य करता था। बिस्तर पर आने से अलकेश साहू का दुकान जाना भी बंद हो गया था। जिससे वह दिव्यांगता के साथ बेरोजगारी का दंश झेल रहा था।

आरडी स्कूल की प्रतिष्ठा और आशुतोष ने राज्य स्तर पर लहराया परचम

राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया

बैतूल। क्वालिटी एजुकेशन में अग्रणी उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान आर.डी. पब्लिक स्कूल बैतूल के मेधावी विद्यार्थियों प्रतिष्ठा सिंह और आशुतोष सिंह ने राज्य स्तर पर सफलता का परचम लहरा कर बैतूल जिले को गौरविन्त किया है। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में 17 एवं 18 नवम्बर को आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल की कक्षा 12वीं की छात्रा कुमारी प्रतिष्ठा सिंह ठाकुर एवं उनके भाई कक्षा 9वीं के छात्र आशुतोष सिंह के विज्ञान मॉडलों ने राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इस उत्कृष्ट सफलता के लिए म.प्र. के खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग सहित अन्य अतिथियों ने प्रतिष्ठा सिंह और आशुतोष सिंह को पुरूस्कृत कर सम्मानित किया गया। राज्य स्तर पर बैतूल जिले का नाम रौशन करने वाले प्रतिभावन भाई-बहन को आरडी पब्लिक स्कूल बैतूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल, प्राचार्य सहित शिक्षकों ने शुभकामनाएं देकर उनका हौसला बढ़ाया है। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के प्रतिभागियों के लिए आयोजित राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता में सबसे कम उम्र के प्रतिभागी बहन-भाई प्रतिष्ठा और आशुतोष सिंह द्वारा ग्रीन एनर्जी एवं आपदा प्रबंधन की थीम पर बनाए गए मॉडल ने प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। उक्त दोनों प्रतिभावान विद्यार्थियों की उत्कृष्ट सफलता के लिए म.प्र. के खेल-युवा कल्याण एवं सहाकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने उन्हे पुरूस्कृत कर सम्मानित किया गया।

बच्चों के समन्वित विकास पर हमारा फोकस : ऋतु खण्डेलवाल

आरडी पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर श्रीमती ऋतु खण्डेलवाल ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सफलता का परचम लहराने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिष्ठा और आशुतोष ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उत्कृष्ट सफलता हासिल कर विद्यालय सहित समूचे जिले को गौरवान्वित किया है। इतनी कम उम्र में विज्ञान के क्षेत्र में राज्य स्तर पर बडी उपलब्धि हासिल करना अत्यंत प्रशंसनीय है। विद्यालय परिवार को दोनो बच्चों पर गर्व है। डायरेक्टर श्रीमती खण्डेलवाल ने कहा कि हमारा फोकस बच्चो के समन्वित विकास पर रहता है। स्कूली पढाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के साथ बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए उनकी अभिरूचि के मुताबिक खेल, कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकि, रिसर्च सहित अन्य क्षेत्रों में उन्हें पारंगत किया जाता है।

कांग्रेस के बीएलए का दो दिवसीय प्रशिक्षण आज से

जिला प्रशिक्षक मोनू वाघ और स्पेंसर लाल करेंगे मार्गदर्शन

बैतूल। मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष व प्रशिक्षण प्रभारी महेंद्र जोशी के निर्देश पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा के मार्गदर्शन में बैतूल जिले की भैंसदेही, घोड़ाडोंगरी और आमला विधानसभा के बीएलए-2 प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 और 21 नवंबर को आयोजित किए जा रहे हैं। जिसमें जिला प्रशिक्षक मोनू वाघ और स्पेंसर लाल प्रशिक्षक के रूप में पूरे दो दिवसीय सत्र में मार्गदर्शन देंगे। प्रशिक्षण में ब्लाक अध्यक्ष, ब्लाक प्रभारी, मंडलम अध्यक्ष, मंडलम प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। पहले दिन 20 नवंबर गुरुवार को दोपहर 12 बजे भैंसदेही ब्लाक व हिडली का प्रशिक्षण उमा लॉन भैंसदेही में होगा। इसके बाद दोपहर 02 बजे भीमपुर व दामजीपुरा ब्लाक का प्रशिक्षण मंगल भवन भीमपुर में आयोजित होगा। तीसरा सत्र दोपहर 03.30 बजे चिचोली ब्लाक के लिए आदिवासी मंगल भवन चिचोली में होगा। दूसरे दिन 21 नवंबर शुक्रवार को सुबह 11 बजे शाहपुर व भौरा ब्लाक का प्रशिक्षण एस.एस. लॉन कुंडी टोल के पास शाहपुर में होगा। दोपहर 01 बजे घोड़ाडोंगरी, पाढर व चोपना ब्लाक का प्रशिक्षण कतिया समाज मंगल भवन घोड़ाडोंगरी में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद दोपहर 02.30 बजे सारनी व सारनी ग्रामीण का प्रशिक्षण कांग्रेस कार्यालय शॉपिंग सेंटर सारनी में रखा गया है, जो आमला विधानसभा के अंतर्गत आता है। दिन का अंतिम सत्र शाम 04 बजे आमला व बोरेदेही ब्लाक के लिए माथनकर लॉन आमला में होगा। दो दिवसीय कार्यक्रम में सभी ब्लाकों के बीएलए को बूथ स्तर पर संगठन की रणनीति, जिम्मेदारियों और चुनावी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

इलेक्ट्रम इंस्टीट्यूट बैतूल के परिसर में एलन इंस्टीट्यूट कोटा की विशेषज्ञ फैकल्टी द्वारा बच्चों को विशेष मार्गदर्शन

बैतूल। जिले के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान इलेक्ट्रम इंस्टीट्यूट बैतूल के गुरुद्वारा रोड स्थित परिसर में विगत दिनों देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलन इंस्टीट्यूट कोटा से आए विषय विशेषज्ञ द्वारा बैतूल के विद्यार्थियों से उच्चस्तरीय शैक्षणिक मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। यह आयोजन हमारे जिले के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान एलन इंस्टीट्यूट कोटा की विशेषज्ञ फैकल्टी ने विद्यार्थियों को आईआईटी-जेईई और नीट तथा बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थित तैयारी के लिए सुझाव और बेहतर रणनीति के मूल मंत्र बताए। इस दौरान भौतिक विज्ञान के अनुभवी विशेषज्ञ डॉ. हृषिकेश शर्मा तथा जीव विज्ञान के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉ. अतिन सर ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद कर कई सुझाव दिए। विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को परीक्षा-पैटर्न, अध्यायवार वेटेज, विषय की गहराई में जाकर अध्ययन, उच्च स्तरीय प्रश्नों को हल करने की सरल विधियाँ, बोर्ड एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को संतुलित करने की रणनीति, बेहतर समय प्रबंधन की ट्रिक और नियमितता के महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगातार अभ्यास, शंकाओं का समय पर समाधान तथा सही दिशा में की गई मेहनत ही सफलता का मूल मंत्र है। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों ने अपने विषयों से जुड़ी कई शंकाएं, जिज्ञासाएँ रखीं, जिनका समाधान विशेषज्ञों द्वारा सहज, स्पष्ट एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया गया। मार्गदर्शन सत्र के बाद विद्यार्थियों में उल्लेखनीय उत्साह, आत्मविश्वास और परीक्षा के प्रति नई दृष्टि देखने को मिली। इलेक्ट्रम इंस्टीट्यूट बैतूल के प्रबंधन की ओर से एलन इंस्टीट्यूट कोटा की फैकल्टी का आभार व्यक्त करते कहा कि जिले के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण गुणवत्ता उपलब्ध कराना संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। प्रबंधन ने समय समय पर ऐसे उच्चस्तरीय शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प भी व्यक्त किया।

पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया विंड एनर्जी प्लांट का शैक्षणिक भ्रमण

बैतूल। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग शाखा के पंचम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को कुकरूखामला स्थित विंड एनर्जी प्लांट का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। इस शैक्षणिक यात्रा का उद्देश्य विद्यार्थियों को पवन ऊर्जा उत्पादन की तकनीकी प्रक्रियाओं, उसके संचालन, रखरखाव एवं आधुनिक ऊर्जा प्रबंधन के ज्ञान से अवगत कराना था। भ्रमण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा विद्यार्थियों को विंड टरबाइन की कार्यप्रणाली, ऊर्जा उत्पादन क्षमता, नियंत्रण प्रणाली तथा नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व की विस्तृत जानकारी दी गई। विद्यार्थियों ने पवन ऊर्जा के क्षेत्र में रोजगार एवं अनुसंधान संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। प्राचार्य डॉ. अरुण सिंह भदौरिया ने बताया कि ऐसे औद्योगिक एवं तकनीकी भ्रमण विद्यार्थियों में तकनीकी समझ बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें वास्तविक कार्यप्रणाली का अनुभव भी प्रदान करते हैं। कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ और विद्यार्थियों का इस भ्रमण से ज्ञानवर्धन हुआ।

पुरुषों में बदनामी का डर और चुप्पी सबसे घातक : डॉ. संदीप गोहे

बैतूल। पुरुष मानसिक स्वास्थ्य और अधिकारों पर 12 साल से काम कर रहे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. संदीप गोहे (संस्थापक एसआईएफ बैतूल) ने इंटरनेशनल मेंस डे पर एनसीआरबी की रिपोर्ट साझा करते हुए बताया कि पिछले पांच साल में 785 विवाहित पुरुष अपनी पत्नी या उसके सहयोगियों द्वारा की गई हिंसा में मारे गए, जिनमें सबसे ज्यादा 198 मामले उत्तर प्रदेश के हैं। हर साल औसतन 275 पति ऐसी घटनाओं के शिकार हो रहे हैं। द लैंसेट के अनुसार रिश्तों आधारित हत्याएं 10-11 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं। डॉ. संदीप गोहे कहते हैं कि कई पुरुष डर, बदनामी और झूठे आरोपों के कारण शिकायत नहीं कर पाते, जो आगे चलकर घातक साबित होता है। वे जेंडर-न्यूट्रल कानून, झूठे मामलों पर कड़ा दंड और पुरुष पीड़ितों के लिए काउंसलिंग व्यवस्था की जरूरत बताते हैं। समाज पुरुषों के संघर्ष और मानसिक स्वास्थ्य पर बात करने से अब भी कतराता है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी हैं कि विवाह से पहले स्पष्ट बातचीत करें, व्यवहार पर ध्यान दें, और किसी भी दबाव या धमकी को हल्के में न लें। क्योंकि वैवाहिक संबंधों के भीतर हिंसा का एक कम चर्चित लेकिन तेजी से बढ़ता रूप सामने आ रहा है। डॉ. गोहे कहते हैं कि पीड़ित चाहे महिला हो या पुरुष, न्याय और सुरक्षा का अधिकार सभी को समान मिलना चाहिए।

पैक्स एवं स्व-सहायता समूह से खुलेगा ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय

मंत्री सारंग ने ली सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक

भोपाल (नप्र)। सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को मंत्रालय में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीपीपीपी अंतर्गत जीआईएस-2025 के दौरान हुए एमओयू की प्रगति, नवाचार प्रकोष्ठ की गतिविधियों तथा सहकारिता तंत्र को मजबूत बनाने से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि पैक्स और स्व-सहायता समूहों के बीच सहयोगात्मक ढांचा तैयार कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े अवसर विकसित किए जा सकते हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि पैक्स-स्व सहायता समूह के बीच साझेदारी का स्पष्ट एवं क्रियाशील रोडमैप तैयार किया जाए। जिससे ग्रामीण स्तर पर नए रोजगार व उद्यमों को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारिता ही वह सशक्त नेटवर्क है जो हर घर तक आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को पहुँचा सकता है। हमें स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों को पहचानकर योजनाओं को धरातल पर उतारना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नवाचार की सक्सेस स्टोरी तैयार की जाए। इस नवाचार को दस्तावेज़ रूप में भी संकलित किया जाए।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि जिला स्तर पर सहकारी बैंकों के सीईओ के माध्यम से किसानों, सहकारी समितियों के प्रबंधकों तथा अन्य संबंधित हितधारकों से सुझाव एकत्र किए जाएं। जिससे मुख्यालय से आवश्यक सुधार करते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके।

बैठक में प्रमुख सचिव सहकारिता श्री डी.पी. आहूजा, आयुक्त सहकारिता श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक (उपभोक्ता संघ) श्री ऋतुराज रंजन, प्रबंध संचालक (बीज संघ) श्री महेंद्र दीक्षित, प्रबंध संचालक (अपेक्स बैंक) श्री मनोज गुप्ता सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

कलार समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 23 को

भोपाल। वरिष्ठ नागरिक मंच कलार समाज म.प्र. भोपाल एवं एलएनसीटी समूह के तत्वावधान में, कलचुरी समाज के सभी सामाजिक संगठनों के सहयोग से चतुर्थ निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 23 नवंबर को एलएनसीटी विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित किया जाएगा। मीडिया प्रभारी राजेश राय ने बताया कि सम्मेलन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। समारोह में पंजीकृत 11 जोड़े समाज के संतजनों से आशीर्वाद प्राप्त कर नवजीवन की शुरुआत करेंगे। मंच ने समाजजनों से आग्रह किया है कि वे इस महाअनुष्ठान में पहुँचकर वर-वधुओं को गृहस्थ जीवन प्रारंभ करने हेतु उपहार व आशीर्वाद प्रदान करें तथा पुण्य लाभ अर्जित करें।

11 रथों की भव्य सामूहिक बारात आकर्षण का केंद्र- इस वर्ष सम्मेलन में विशेष रूप से तैयार की गई सामूहिक बारात आकर्षण का केंद्र रहेगी। सभी 11 जोड़े अलग-अलग रथों पर बैठकर बारात में शामिल होंगे। आगे आयोजक और बाराती डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए चलेंगे, वहीं आयोजन समिति घराती बनकर पारंपरिक तरीके से बारात का स्वागत व सत्कार करेगी।ड्रेस कोड के साथ दिखेगी समाज की एकरूपता। कार्यक्रम में समाज की एकता दर्शाने हेतु विशेष ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है।

बर्फीली हवा से ठिठुरा मप्र 21 जिलों में आज शीतलहर

प्रदेश में 10 डिग्री से नीचे पारा...राजगढ़ सबसे ठंडा, भोपाल-इंदौर में फिर लुढ़का

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश में तेज ठंड का दौर बरकरार है। मंगलवार-बुधवार की रात प्रदेश के कई शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे ही रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा दर्ज किया गया। यहां पारा 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल और इंदौर में पारे में फिर गिरावट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार-बुधवार की रात में भोपाल में 7.8 डिग्री, इंदौर में 6.9 डिग्री, ग्वालियर में 10.7 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री और जबलपुर में 9.9 डिग्री रहा। इसी तरह पचमढ़ी में 6.6 डिग्री, नौगांव में 8 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, खरगोन में 9.4 डिग्री, छिंदवाड़ा-मलाजखंड में 9.6 डिग्री और रीवा में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाकी शहरों में 10 से 13 डिग्री के बीच पारा टिका रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, जबलपुर, शाजापुर, सीहोर, देवास, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, मैहर, शहडोल, कटनी, उमरिया में कोल्ड वेव चलने का अलर्ट जारी किया है।

राजधानी में टूट चुका 84 साल का रिकॉर्ड

इससे पहले सोमवार-मंगलवार की रात में कई शहरों में पारे में गिरावट का दौर जारी रहा। 18 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम रहा। राजगढ़ सबसे ठंडा रहा। यहां पारा 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 6.4 डिग्री रहा। उमरिया में 7.6 डिग्री, नौगांव में 7.8 डिग्री, शिवपुरी में 8 डिग्री, बैतूल में 8.7 डिग्री, धार में 8.8 डिग्री, मलाजखंड में 8.9 डिग्री, खंडवा में 9.4 डिग्री, छिंदवाड़ा में 9.5 डिग्री, खरगोन-मंडला में 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में पारे में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। रविवार-सोमवार की रात यहां तापमान रिकॉर्ड 5.2 डिग्री था। इससे नवंबर की सर्दी का 84 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया था। इसके बाद तापमान 8.2 डिग्री पर आ गया। इंदौर में 7.7 डिग्री, ग्वालियर में 10.5 डिग्री, उज्जैन में 11 डिग्री और जबलपुर में पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

शहडोल में ठंड से एक व्यक्ति की मौत

मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है है। इस बीच शहडोल जिले में 45 साल के एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शॉर्ट पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ठंड बताई गई है। शहडोल में पिछले कुछ दिनों से न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। वार्ड नंबर 30 के कट्टी मोहल्ला के रहने वाले बबलू सिंह गुब्बारे बेचते थे। पत्नी की पहले ही मौत हो चुकी है। दो बेटियां हैं। मंगलवार रात करीब 9 बजे बबलू ने बेटियों के साथ खाना खाया। बेटियों को सुलाने के बाद खुद फर्श पर पर बिस्तर लगाकर सो गए। बबलू आमतौर पर रोज सुबह 7 बजे उठ जाते थे। बुधवार को सुबह आठ बजे तक सोकर नहीं उठे तो बेटियों ने उन्हें जगाने की कोशिश की। जब वे नहीं उठे तो बेटियों ने पड़ोसियों को ये बात बताई। लोगों ने बबलू को हिला-डुलाकर देखा। शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी।

सटीक निशाना, अटूट धैर्य—कुशाग्र ने जीता अंतर्राष्ट्रीय सम्मान

● 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट में हासिल किया कांस्य पदक

भोपाल (नप्र)। टोक्यो में आयोजित 25वीं समर डेफलंपिक में भारत तथा मध्यप्रदेश के लिए मध्यप्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के प्रतिभावान शूटर कुशाग्र सिंह राजावत ने गौरवपूर्ण उपलब्धि दर्ज कराई है। शूटर कुशाग्र सिंह ने 50 मीटर राइफल प्रोन (पुरुष वर्ग) स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत कांस्य पदक जीता। इस उपलब्धि से अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी मंच पर मध्यप्रदेश का गौरव बढ़ाया है।

शानदार प्रदर्शन से चमका मध्यप्रदेश का सितारा

कुशाग्र सिंह राजावत ने प्रतियोगिता के दौरान अपनी उत्कृष्ट तकनीक, धैर्य और सटीकता का अद्वितीय प्रदर्शन किया। कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी माहौल में भी उन्होंने संतुलित खेल दिखाते हुए पदक तालिका में स्थान बनाकर देश एवं प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उनके इस प्रदर्शन ने युवाओं के लिए प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

मंत्री काश्यप ने अनुकंपा नियुक्ति पत्र किए वितरित

भोपाल (नप्र)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चेतन्य कुमार काश्यप ने बुधवार को विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लाभांवित परिवारजन ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्य शासन का आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री काश्यप ने सहायक ग्रेड वर्ग-3 के पद पर सर्वश्री शुभम सोनकर, जकाउल्ला और सुश्री समृद्धि शर्मा को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री लोकेश मोहार को भृत्य के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई है। इस अवसर पर विभाग के संयुक्त संचालक श्री अंबरीश अधिकारी भी उपस्थित थे।

जीएमसी का हेल्थ इंश्योरेंस की स्थिति पर रिपोर्ट

● 33.6 प्रतिशत परिवार अब भी बिना बीमा

भोपाल (नप्र)। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के ताजा अध्ययन ने शहर और गांव के बीच स्वास्थ्य बीमा कवरेज में मौजूद गहरी खाई को उजागर कर दिया है। रिसर्च में शामिल 428 परिवारों में से 33.6 प्रतिशत अभी भी किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल नहीं हैं, जिसमें शहरी परिवारों की हिस्सेदारी ग्रामीणों से अधिक पाई गई। आयुष्मान भारत योजना सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली स्कीम है, लेकिन पात्र होने के बावजूद कई लोगों के कार्ड नहीं बन पाए। अध्ययन में सामने आया कि बायोमेट्रिक मिलान की समस्या, अधूरे दस्तावेज और जानकारी का अभाव आयुष्मान कवरेज बढ़ने में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। प्रो. डॉ. जीवन सिंह मीणा के मार्गदर्शन में डॉ. कुलदीप गुप्ता द्वारा किए गए में 214 ग्रामीण (औबेदुल्लागंज) और 214 शहरी परिवारों (लेडी थोर सेंटर कैचमेंट एरिया) को शामिल किया गया।

शहरी सोशल मीडिया से, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मियों से सीख रहे- अध्ययन से पता चला कि शहरी क्षेत्रों में 48.8 प्रतिशत प्रतिभागियों को परिवार और मित्रों से बीमा की जानकारी मिली। जबकि 27.3 प्रतिशत को सोशल मीडिया से मिलती है।

फैसल मलिक, दिव्या दत्ता, समेत कई की हस्तियां पहुंचेंगी भोपाल

27-29 नवंबर तक भोपाल में सजेगा विश्वरंग-2025 का रंगरंग मंच

भोपाल (नप्र)। भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति और भारतीय भाषाओं को वैश्विक पहचान दिलाने के उद्देश्य से विश्व रंग फाउंडेशन और रवींद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से विश्वरंग-टैगोर अंतरराष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव 2025 का आयोजन 27 से 29 नवंबर तक रवींद्र भवन, भोपाल में कर रहे हैं। यह विश्वरंग का सातवां संस्करण है, जिसमें देश-विदेश के नामचीन साहित्यकार, कलाकार, शिक्षाविद और सांस्कृतिक हस्तियां शामिल होंगी।

तीन दिवसीय महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की विशेष श्रृंखला रहेगी। 27 नवंबर को श्रीराम कला केंद्र, नई दिल्ली 'श्री कृष्ण लीला' नृत्य नाटिका का मंचन करेगा। 28 नवंबर को देश के लोकप्रिय समूह कलेक्टिव क्वॉयर प्रस्तुति देगा, जबकि 29 नवंबर को गायिका सोना महापात्रा विशेष संगीत संध्या में श्रोताओं को सुरों से मंत्रमुग्ध करेंगी।

विचार और संवाद सत्रों में पहुंचेंगी हस्तियां- 28 नवंबर को अभिनेता फैसल मलिक, अभिनेत्री दिव्या दत्ता, सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और उद्यमी अंकुर वारिकू, गीतकार स्वानंद किरकिरे और क्रिकेटर-कॉमेंटेटर आकाश चोपड़ा अपने विचार रखेंगे। 29 नवंबर को अभिनेत्री सान्या मल्होत्रा, पत्रकार सौरभ द्विवेदी और अन्य चर्चित हस्तियां सहभागिता दर्ज कराएंगी।

साहित्य की बड़ी आवाजें भी एक मंच पर- देवदत्त पटनायक, दिव्य प्रकाश दुबे, ममता कालिया, नीलेश मिश्रा, ए. अरविंदाक्षन, शशांक, शिवमूर्ति और ज्ञान चतुर्वेदी जैसे प्रमुख साहित्यकार भी अपने विचार और रचनाएं साझा करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति बनेगी विशेष आकर्षण- नीदरलैंड, शारजाह, श्रीलंका, इजराइल, जापान, डेनमार्क, चीन और इटली से भी साहित्यकार शामिल होंगे। साहित्यकार रामा तक्षक, डॉ. पूर्णिमा वर्मन, अमली, आमिर ओर, बन्या नट्सूइशी, पिया टाफड्राप, मिंग दी और मोनिका गुएरा भी अलग-अलग सत्रों में अपने विचार और रचनाएं साझा करेंगे।

पत्नी-बच्चों के साथ जा रहा युवक सड़क पर गिरा

बड़वानी (नप्र)। बड़वानी में एक सरकारी डॉक्टर ने सड़क पर बेहोश पड़े एक व्यक्ति की जान बचाई। यह घटना बुधवार दोपहर करी रोड स्थित आरटीओ ऑफिस के सामने हुई, जहां पत्नी और बच्चों के साथ जा रहे अंबू बैग नाम का युवक अचानक सड़क पर गिर गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। ड्यूटी पर जा रहे डॉ. किशोर मुकाती ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और अंबू बैग की मदद से उसे कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन देना शुरू किया। तलवाड़ा बुजुर्ग में पदस्थ डॉ. मुकाती ने बताया कि उन्होंने व्यक्ति की पल्स और कैरोटिड चेक की, जो नहीं मिल रही थी। उन्होंने सीपीआर और अंबू बैग से हाइपर वेंटिलेट किया, जिससे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच सके। तीन-चार मिनट बाद व्यक्ति का दिल फिर से धड़कने लगा और थोड़ी देर में उसे होश आ गया।

हाइपोथायरायडिज्म और मोटापा विशेषज्ञ सेंटर में पंजीयन शुरू

भोपाल (नप्र)। भोपाल में आयुष मंत्रालय और शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय की संयुक्त पहल से संचालित हाइपोथायरायडिज्म और मोटापा विशेषज्ञ इकाई एक बार फिर मरीजों के लिए खोल दी गई है। इस विशेष यूनिट में उन 18-60 वर्ष के मरीजों को शामिल किया जाएगा जो थायरॉयड कम होने की समस्या से जूझ रहे हैं और लगातार एलोपैथिक दवाएं लेने के बावजूद वजन नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। यूनिट में पंजीयन से लेकर सभी जांचें, विस्तृत मूल्यांकन, ठहराव और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा। यह व्यवस्था उन मरीजों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, जिनका वजन थायरॉयड दवाओं के बाद भी काबू में नहीं आ पाता। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा मिलकर यह यूनिट संचालित कर रहे हैं। जहां वजन और थायरॉयड असंतुलन से जूझ रहे मरीजों को समग्र और वैज्ञानिक मूल्यांकन के आधार पर होम्योपैथिक उपचार उपलब्ध कराया जाता है।

कॉल पर ही करा सकते हैं पंजीयन- यूनिट के लिए वही मरीज पात्र हैं जिनकी उम्र 18 से 60 वर्ष है। इसके अलावा वे जिन्हें हाइपोथायरायडिज्म है, जो नियमित एलोपैथिक दवा (थायरोक्सिन आदि) ले रहे हैं और इसके बावजूद वजन नियंत्रित नहीं हो पा रहा है। रोगी वीक डे में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक फोन नंबर 0755-2992970 पर कॉल करके अपना पंजीयन करा सकते हैं।

एमपी में सिविल जज की भर्ती परीक्षा पर विवाद

कांग्रेस ने उठाए सवाल, 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ

भोपाल (नप्र)। एमपी में सिविल जज परीक्षा 2022 को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सिविल जज के कुल 191 पदों में से 121 पद आदिवासी का चयन न होने पर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है।

आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉ विक्रांत भूरिया ने एमपी आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम के साथ भोपाल प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भूरिया ने इस भर्ती परीक्षा को आरक्षित वर्ग के लिए दोबारा कराकर आदिवासी उम्मीदवारों को शामिल करने की मांग की। हमारी आपत्ति साफ है कि आदिवासियों को धीरे-धीरे सिस्टम से बाहर किया जा रहा है। उनके लिए सिस्टम के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सिविल जज परीक्षा 2022 के परिणाम हैं। उनमें 191 पोस्ट थीं उसमें से 121 पद आदिवासियों के लिए आरक्षित थीं। इन 121 पदों पर एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ। मतलब जिस राज्य में पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। उस राज्य में इन्हें एक भी आदिवासी सिविल जज के लिए पात्र आदिवासी उम्मीदवार नहीं मिला। ये अपने आप में सरकार के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है।

मप्र सिविल जज-2022 परिणाम आदिवासी युवाओं के साथ सुनियोजित अन्याय का प्रतीक- विक्रांत भूरिया मध्यप्रदेश सिविल जज-2022 के परिणाम ने पूरे आदिवासी समाज को गहरे आघात में डाल दिया है। कुल 191 पदों में से 121 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित थे, लेकिन इन 121 आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं होना केवल एक प्रशासनिक 'विफलता' नहीं, बल्कि सिस्टम में गहरे बैठे पक्षपात और संरचनात्मक भेदभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। यह सवाल केवल इतना भर नहीं है कि परिणाम क्या आया, असली सवाल यह है कि क्या सचमुच 121 सीटों पर एक भी योग्य आदिवासी युवा नहीं मिला या फिर चयन प्रक्रिया और पूरी प्रणाली ने उन्हें शुरुआत की सीढ़ी पर ही रोक दिया। पिछले चार वर्षों से लगातार एक ही पैटर्न सामने आ रहा है कि सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में एसटी उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की सीढ़ी तक पहुँचने ही नहीं दिया जाता, प्रारंभिक चरणों में ही ऐसे मानक, कटऑफ और प्रक्रियाएँ लागू की जाती हैं जिनके चलते आदिवासी युवाओं को व्यवस्थित रूप से बाहर कर दिया जाता है।

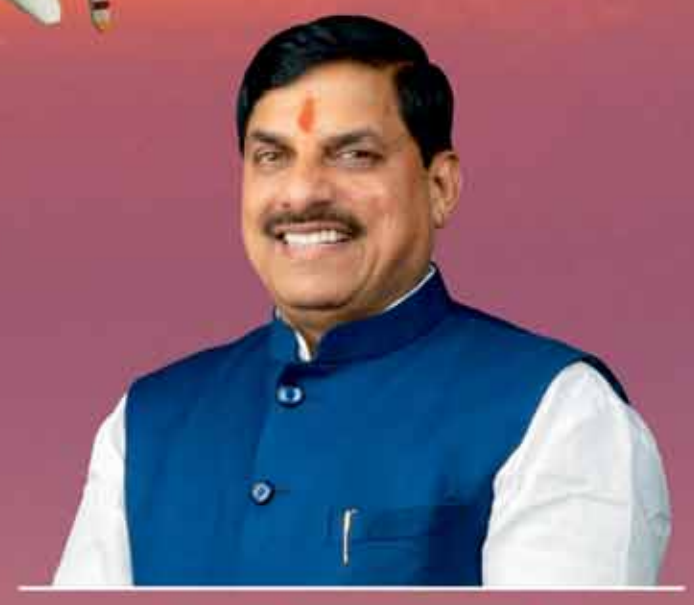

The heart of Incredible India
डॉ. मोहन यादव का
अभ्युदय मध्यप्रदेश
मध्यप्रदेश पर्यटन
अब और अद्‌भुत
आज से शुरू
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री
डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री
पीएमश्री हेली पर्यटन सेवा
देश में अंतर-राज्यीय वायु सेवा संचालित करने वाला
पहला राज्य मध्यप्रदेश
सप्ताह में 5 दिन संचालन
ईको-टूरिज्म सेक्टर भोपाल - पचमढ़ी - मढ़ई
वाइल्ड लाइफ सेक्टर जबलपुर - कान्हा - बांधवगढ़
स्पिरिचुअल सेक्टर इंदौर - उज्जैन - ओंकारेश्वर
पीएमश्री वायु पर्यटन सेवा
सप्ताह में 6 दिन संचालन
हेरिटेज सेक्टर
भोपाल - रीवा - सतना
सिंगरौली - खजुराहो
D-11144/25
Booking Links www.flyola.in | air.irctc.co.in | transbharat.in
मध्यप्रदेश जनसंपर्क द्वारा जारी
आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025